

विकसित भारत के निर्माण की राह... 'आत्मनिर्भरता'

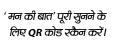


हर महींने के आस्विरी रविवार को रेडियो पर प्रसारित होने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोढ़ी और नागरिकों के बीच सीधे संवाद का माध्यम है, जिसमें समाज, नवाचार और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर चर्चा होती है। 27 ज़्लाई को प्रधानमंत्री मोढ़ी ने मन की बात कार्यक्रम में देश की सफलताओं और देशवासियों की उपलब्धि पर बात की। कार्यक्रम के 124वीं कड़ी में पीएम मोढ़ी ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण के मुद्धों पर बात की तो विज्ञान, विरासत और विविधता का संदेश भी दिया। प्रस्तुत हैं संपादित अंश...

,

- शुभांशु शुक्ला: शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी को लेकर देश में बहुत चर्चा हुई। जैसे ही शुभांशु धरती पर सुरक्षित उतरे, लोग उछल पड़े, हर दिल में ख़ुशी की लहर दौड़ गई। विज्ञान और अंतरिक्ष को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी है। अब छोटे-छोटे बच्चे भी अंतरिक्ष की बात करते हैं।
- स्पेस स्टार्टअप : देश में स्पेस स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहे हैं। पांच साल पहले 50 से भी कम स्टार्टअप थे। सिर्फ स्पेस सेक्टर में आज 200 से ज्यादा हो गए है। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे है।
- नई ऊर्जा: 21वीं सदी के भारत में आज विज्ञान एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले हमारे छात्रों ने इंटरनेशनल केमिस्टी ओलंपियाड में मेडल जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हुए इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे छात्रों ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है।
- मुंबई में ओलंपियाड: मुंबई में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड होने जा रहा है। इसमें 60 से ज्यादा देशों के छात्र आएंगे, वैज्ञानिक भी आएंगे। यह अब तक का सबसे बडा ओलंपियाड होगा।
- खुदीराम बोस : बिहार का मुजफ्फरपुर शहर। तारीख, 11 अगस्त 1908 हर गली, हर चौराहा, हर हलचल उस समय जैसे थम सी गई थी जब सिर्फ 18 साल की उम्र में खदीराम बोस ने ऐसा साहस दिखाया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तब अखबारों ने भी लिखा था - "खुदीराम बोस जब फांसी के फंदे की ओर बढ़े, तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी।"
- राष्ट्रीय हथकरघा दिवस: 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' के 10 साल पूरे हो रहे हैं। आजादी की लड़ाई के समय जैसे हमारी

- खादी ने आजादी के आंदोलन को नई ताकत दी थी. वैसे ही आज जब देश, विकसित भारत बनने के लिए कदम बढ़ा रहा है, तो टेक्सटाइल सेक्टर देश की ताकत बन रहा है।
- हथकरघा टेक्नोलॉजी : बिहार के नालंदा से नवीन कुमार की उपलब्धि प्रेरणादायक है। उनका परिवार पीढ़ियों से हथकरघा के काम से जड़ा है। सबसे अच्छी बात यह कि उनके परिवार ने अब इस फील्ड में आधुनिकता का भी समावेश किया है। अब उनके बच्चे हथकरघा टेक्नोलॉजी की पढाई कर रहे हैं।
- ज्ञान भारतम् मिशन : इस वर्ष के बजट में एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा की गई है 'ज्ञान भारतम् मिशन'। इस मिशन में प्राचीन पांडलिपियों को डिजिटाइज किया जाएगा। फिर एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी बनाई जाएगी। जहां दुनियाभर के विद्यार्थी, शोधकर्ता, भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे।
- आत्मनिर्भर भारत : आज भारत में 3,000 से ज्यादा टेक्सटाइल स्टार्टअप सक्रिय हैं। 2047 के विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और 'आत्मनिर्भर भारत' का सबसे बड़ा आधार है - 'वोकल फॉर लोकल।' जो चीजें भारत में बनी हों, वही खरीदें और वही बेचें। यह हमारा संकल्प होना चाहिए।
- स्वच्छ भारत मिशन : जब देश एक सोच पर एक साथ आ जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। 'स्वच्छ भारत मिशन' इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जल्द ही इस मिशन को 11 साल परे होंगे। इसकी ताकत और इसकी जरूरत आज भी वैसी ही है। इन 11 वर्ष में 'स्वच्छ भारत मिशन' एक जन-आंदोलन बना है।





न्यू इंडिया **समाचार**

वर्षः 6, अंकः 04 । 16-31 अगस्त, 2025

प्रधान संपादक धीरेन्द्र ओझा

प्रधान महानिदेशक पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

मुख्य सलाहकार संपादक

संतोष कुमार

सलाहकार संपादक

विभोर शर्मा

वरिष्ठ सहायक सलाहकार संपादक

पवन कुमार

सहायक सलाहकार संपादक

अखिलेश कुमार चन्दन कुमार चौधरी

भाषा संपादन सुमित कुमार (अंग्रेजी) रजनीश मिश्रा (अंग्रेजी) नदीम अहमद (उर्दू)

चीफ डिजाइनर

श्याम तिवारी

सीनियर डिजाइनर

फूलचंद तिवारी

डिजाइनर

अभय गुप्ता सत्यम सिंह



13 भाषाओं में उपलब्ध न्यू इंडिया समाचार को पढ़ने के लिए क्लिक करें।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

न्यू इंडिया समाचार के पुराने अंक पढ़ने के लिए क्लिक करें

https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx



न्यू इंडिया समाचार के बारे में लगातार अपडेट के लिए फॉलो करें: @NISPIBIndia

अंदर के पन्नों पर...



आवरण कथा



खेलता भारत खिलता भारत बीते 11 वर्ष में कई क्रांतिकारी परिवर्तनों ने खेलों में बदलाव की नई गाथा लिखी है। अब भारत को वैश्विक स्तर पर खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार ने मंजूर की राष्ट्रीय खेल नीति 2025... 14-29

विरासत का संरक्षण

विकास के शिखर की ओर बढ़ता तमिलनाडु



पीएम मोढ़ी ने 4,800 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत में तमिलनाडु के योगढ़ान को किया नमन... | 30-32

समाचार सार 4-5

संसद में चर्चा : ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा

लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा भारत का पक्ष व्यक्तित्व - बीपी मंडल

.....

6-11

12-13

जिन्होंने दिलाया पिछड़े वर्ग को न्याय

पीएम जन धन के 11 वर्ष

जानिए जन धन योजना कैसे बनी सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का आधार | 33-35

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त

11 वर्ष के ठोस कदम, जिन्होंने बदली अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की तस्वीर | 36-40

बिहार के संसाधन बिहार की प्रगति

पीएम मोदी ने बिहार को सौपीं 7 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की सौगातें | 41-43

भारत विकास पथ पर, पीएम बोले-आमार बंगाल होबे इंजन

पीएम मोदी ने 5,400 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की दी सौगात | 44-45

सहकारिता के साथ देश के भविष्य को नया आकार

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण | 46-47

पीएम मोदी का ब्रिटेन और मालदीव दौरा

ब्रिटेन के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर तो मालदीव में दोस्ती का एक और अध्याय | 48-51

राष्ट्र निर्माण के 'अटल' आदर्श

अटल जी को 7वीं पुण्यतिथि पर नमन

|52-54

सहकारी समितियां होंगी सशक्त, 4 रेलवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में छह अहम प्रस्तावों को मंजूरी 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार घोषित

|56

| 55

प्रकाशक और मुद्रकः कंचन प्रसाद, महानिदेशक, सीबीसी (केंद्रीय संचार ब्यूरो)। **मुद्रणः** जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा. लि., बी-278, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020। **पत्राचार और ईमेल के लिए पताः** कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्लेक्स, नई दिल्ली- 110003। **ईमेल-** response-nis@pib.gov.in आर. एन. आई. नंबर DELHIN/2020/78812

संपादक की कलम से...

खेल बना राष्ट्र-समाज की संस्कृति का हिस्सा

सादर नमस्कार।

ओलंपिक-पैरालंपिक हो या अन्य विश्व स्तरीय खेल प्रतिस्पर्धा, राष्ट्र का गौरव बनने वाले खिलाड़ी सहज ही तैयार नहीं हो जाते। इनकी अपनी प्रतिभा, समर्पण, दृढ़ निश्चय और हार न मानने की भावना को जब परिवार, समाज एवं राष्ट्र के समर्थन एवं प्रोत्साहन का बल मिलता है, तब जाकर कोई चैंपियन बन पाता है। आज हम गर्व के साथ भारतीय खिलाड़ियों को लगातार प्रतिस्पर्धाओं में अपनी पहचान बनाते देख रहे हैं।

यह उपलब्धि कुछ मेडल-मात्र की उपलब्धि नहीं है। यह द्योतक है भारत के विकास की, विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर हमारे अग्रसर होने की। विश्व के उच्चतम शिखर पर पहुंचने के लिए किसी देश को सैन्य शक्ति या आर्थिक शक्ति होने के साथ ही जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अग्रणी होना पड़ेगा और खेल एक ऐसा ही अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

निरोगी शरीर, स्वस्थ मानस, सकारात्मक मानसिकता वाले खुले समाज और एक सबल, सफल राष्ट्र के निर्माण में खेल की बड़ी भूमिका है। खेल दूसरों को स्वीकारते हुए, टीम भावना तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का सृजन करता है। अनुशासन एवं हार न मानने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक समाज में खेल का बड़ा महत्व है।

इसी महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार 'खेलो इंडिया' के माध्यम से युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षण, छात्रवृति आदि की सुविधाएं प्रदान कर रही है, ताकि खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को उजागर कर सकें। सरकार के इन प्रयासों से लोगों की धारणाओं में बदलाव आया है, प्रोत्साहन की संस्कृति को बढ़ावा मिला है। खेलो इंडिया का मंत्र आज राष्ट्र समाज की संस्कृति का हिस्सा बन गया है। आज खेल के प्रति हमारे युवाओं में एक नया रुझान, नया उत्साह दिखता है। साथ ही यह विश्वास कि राष्ट्र उनके सपनों को उड़ान देने में उनकी पूरी सहायता करेगा।

हाल में ही सरकार राष्ट्रीय खेल नीति (खेलो भारत नीति 2025) लेकर आई है। नीति में प्रतिभाओं की पहचान, मार्गदर्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, प्रतिस्पर्धी लीग और प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना शामिल हैं। इसका उद्देश्य देश के खेल परिदृश्य को नया स्वरूप देना और खेलों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना है।

29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के संदर्भ में पत्रिका का यह अंक खेलो भारत नीति 2025, देश में खेल परिदृश्य के इसी बदलाव तथा विगत 11 वर्षों की इस यात्रा को अपने पाठकों के समक्ष लेकर आ रही है।

इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने वाले बीपी मंडल, फ्लैगशिप में जन धन योजना के 11 वर्ष, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा सहित उनके पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है।

साथ ही, पत्रिका के इनसाइड पेज पर मन की बात और बैक कवर पर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों के रूप में मान्यता दिए गए मराठा सैन्य विरासत के 12 किलों को समाहित किया गया है।

आप अपना सुझाव हमें भेजते रहिए।

(धीरेन्द ओझा)



हिंदी, अंग्रेजी व अन्य 11 भाषाओं में उपलब्ध पत्रिका पढ़ें/डाउनलोड करें। https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

आपकी बात...





सम-सामयिक विषयों की मिलती है सही जानकारी

मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूं और नियमित रूप से न्यू इंडिया समाचार पित्रका पढ़ता हूं। यह पित्रका मुझे डाक के माध्यम से मिलती है। इस पित्रका के अंक बेहतरीन होते हैं। इससे मुझे सम-सामियक विषयों की सही जानकारी मिलती है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर मैं अपडेट रहता हूं।

शांतनु मंडल

mondal.santanu97@gmail.com

नियमित रूप से पढ़ता हूं न्यू इंडिया समाचार पत्रिका

मैं नियमित रूप से न्यू इंडिया समाचार पत्रिका पढ़ता हूं। इसके माध्यम से मैं केंद्र सरकार की सभी योजनाओं और विकास संबंधी तथ्यों से अपडेट रहता हूं। सरकार का दृष्टिकोण है कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों की मदद करना, पीएम मोदी के नजरिए के साथ यह बखूबी पूरा हो रहा है।

logendranranganathan@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित ज्ञानवर्धक लेख पढ़ने के लिए रहता हूं उत्सुक

न्यू इंडिया समाचार पित्रका में मुझे रेडियो के बारे में पढ़ने का अवसर मिला। यह सुविचारित और समृद्ध इतिहास से जुड़ा हुआ था। आपने कई ऐसी बातें बताईं, जिन्हें मैं आने वाले वर्षों तक याद रखूंगा। मैं आपके अगले ज्ञानवर्धक लेख को पढ़ने के लिए उत्सुक हूं। यह सरकार के कदमों के बारे में एक ज्ञानवर्धक पित्रका है।

sbhatnagar1971@gmail.com

सरकार के कामकाज की विस्तृत जानकारी वाली शानदार पत्रिका

वृद्धावस्था के कारण मुझे पढ़ने में कठिनाई होती है, बावजूद इसके मैं कभी-कभी ऑनलाइन न्यू इंडिया समाचार पत्रिका पढ़ता हूं। यह एक शानदार पत्रिका है, जिसमें सरकार के कामकाज के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है।

गौरीशंकर वैश्य विनम्र gsvaish51@gmail.com

केंद्र सरकार के कार्यों के बारे में सूचना का खजाना है न्यू इंडिया समाचार

मुझे न्यू इंडिया समाचार पत्रिका पढ़ने को मिली। मुझे यह पत्रिका काफी पसंद आई। इसमें केंद्र सरकार द्वारा क्रियीन्वित किए जा रहे कल्याण कार्यक्रम शामिल हैं। यह सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में सूचना का खजाना है। पत्रिका में सभी वर्तमान घटनाक्रम और बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है।

निरंजन जाटोलिया niranjanjatoliya@gmail.com

पत्राचार और ईमेल के लिए पता: कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्लेक्स, नई दिल्ली- 110003. ईमेल- response-nis@pib.gov.in



न्यू इंडिया समाचार को आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर शानिवार-रविवार को द्योपहर 3:10 से 3:25 बजे तक सुनने के लिए **QR** कोड स्कैन करें।



子 上 内 上 内 上 大 上 大

127 साल' बाद' भारत' लोटी' भगवान' 'बुद्ध की पिपरहवा निशानियां



विदेशों से भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को वापस लाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता में एक और नया अध्याय जुड़ा है। इस बार हांगकांग में नीलाम होने जा रहीं भगवान बुद्ध से जुड़ीं पिपरहवा निशानियों को 127 वर्ष बाद वापस भारत लाया गया है। बता दें कि लगभग ढाई हजार वर्ष पहले भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों का एक भाग किपलवस्तु के लोगों को मिला था। पिपरहवा के एक स्तूप में इन्हें सुरक्षित रखा गया। इतिहासकारों के अनुसार ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेपे ने वर्ष 1898 में खुदाई में निकाली गई इन निशानियों को औपनिवेशिक नीति के तहत अपने पास रख लिया। उनके वंशज हांगकांग में इसी साल मई में इन्हें नीलाम करने वाले थे लेकिन, भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद इन्हें स्वदेश वापस लाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए यह जानकारी दी और लिखा कि यह हमारी गौरवशाली संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के संरक्षण और सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। गौरतलब है कि 2014 से अब तक कुल 640 प्राचीन धरोहरें भारत लाई जा चुकी हैं, जबकि इससे पहले 1947 से 2014 के बीच रिफ 13 धरोहरों को ही वापस लाया जा सका था।

बढ़ती डिजिटल साक्षरता... लक्ष्य से ज्यादा व्यक्ति किए प्रशिक्षित

सरकारी सेवाएं हों या निजी क्षेत्र, डिजिटलाइजेशन से आम लोगों के जीवन में सुगमता आई है तो सेवाओं में पारदिशंता को भी बढ़ावा मिला है। विशेषतौर पर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता के माध्यम से सरकार आमजन की राह और आसान कर रही है। वर्ष 2017 में इसी दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों में 6 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) की शुरुआत की गई थी। अपने लक्ष्य से कहीं आगे बढ़कर इस महाभियान में अभी तक 6.39 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसमें अनुसूचित जाति के 1.17 करोड़, अनुसूचित जनजाति के 56 लाख और ओबीसी के 2.55 करोड़ लोग शामिल हैं। यहीं नहीं, घर के नजढ़ीक डिजिटल सेवा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ अब तक शुरू किए गए 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में से 2.92 लाख अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल इलाकों में खोले गए हैं। इसके साथ ही भारतनेट कार्यक्रम के अंतर्गत 2.14 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को भी हाई-स्पीड बॉडबैंड से जोड़ दिया गया है।

डीआरडीओ का परीक्षण सफल भारत ने ड्रोन से दागी मिसाइल

रक्षा क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्मरता के साथ स्वदेशी तकनीक के विकास की राह पर आगे बढ़ रहे भारत को अपनी सैन्य तैयारियों में एक और सफलता



मिली है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल स्थित राष्ट्रीय मुक्त क्षेत्र रेंज में ड्रोन के जरिए प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल वी-3 दागने का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

(डीआरडीओ) का परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। यह डीआरडीओ की ओर से पहले विकसित मिसाइल का उन्नत संस्करण है। वहीं, जिस ड्रोन से इसे ढागा गया उसे बेंगलुरु के स्टार्टअप न्यूस्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। इस मिसाइल में तीन प्रकार के मॉड्यूलर वारहेड विकल्प उपलब्ध हैं; जिनमें आधुनिक टैंकों को नष्ट करने की क्षमता वाला एंटी-आर्मर वारहेड, किलेबंद ठिकानों और भूमिगत संरचनाओं को भेदने की विशेष क्षमता वाला एंटी-बंकर वारहेड के साथ प्री-फ्रैगमेंटेशन वारहेड शामिल है।

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बड़ी कामयाबी, समुद्र के नीचे 21 किमी लंबी सुरंग का पहला खंड खुला



देश की पहली बुलेट ट्रेन को लेकर काम तेजी से चल रहा है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का पहला खंड खोल दिया गया है। रेल मंत्रालय के अनुसार, यह सुरंग बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स को घनसोली होते हुए ठाणे के शिलफाटा से जोड़ती है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के अंतर्गत हाल ही में 310 किलोमीटर लंबे विशेष पुल वायडक्ट यानी एलिवेटेड बिज का निर्माण कार्य भी पूरा किया गया है। ट्रैक बिछाने, ओवरहेड बिजली के तारों, स्टेशनों और पुलों को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। प्रोजेक्ट को लेकर इस बात पर भी सहमति बनी है कि जापान में जहां शिंकानसेन तकनीक के साथ तैयार ट्रैक पर ई-5 बुलेट ट्रेन चलाई जा रही हैं, वहीं भारत में इसी तकनीक से बन रहे मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर पर अगली पीढ़ी की ई-10 बुलेट ट्रेन चलाई जाएंगी।

अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात में चीन से आगे निकला भारत



मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी योजनाओं का परिणाम है कि भारत अब उन औद्योगिक क्षेत्रों में नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जिनमें इससे पहले कभी उसे मैन्युफैक्चरर तक नहीं माना जाता था। रिसर्च फर्म कैनालिस की एक रिपोर्ट के अनुसार इस कैलेंडर वर्ष की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल-जून में भारत ने अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले स्मार्टफोन के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। अब अमेरिका में आयातित स्मार्टफोन में मेड इन इंडिया स्मार्टफोन की हिस्सेदारी 44 प्रतिशत हो गई है, जबिक 2024 की दूसरी तिमाही में यह केवल 13 प्रतिशत थी। वहीं, इसकी तुलना में अमेरिकी बाजार में मेड इन चाइना स्मार्टफोन की हिस्सेदारी इस दौरान एक साल पहले के 61 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत रह गई है।



मेरी पंचायत पुप को जिनेवा में मिला चैंपियन पुरस्कार

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित "मेरी पंचायत" मोबाइल एप्लिकेशन ने जिनेवा में वर्ल्ड समिट ऑन द इन्फॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार २०२५ में चैंपियन पुरस्कार जीता है। यह उपलब्धि भारत के डिजिटल और समावेशी ग्रामीण विकास मॉडल की वैश्विक मान्यता है। सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने वाले इस एप को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में सम्मानित किया गया है। 'मेरी पंचायत एप - भारत की पंचायतों के लिए एम-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म' भारत की २.६५ लाख ग्राम पंचायतों के 25 लाख से ज्यादा निर्वाचित प्रतिनिधियों और लगभग ९५ करोड ग्रामीण निवासियों को सशक्त बनाता है। 12 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध इस एप के जरिए नागरिक अपने मोबाइल पर पंचायत बजट और विकास योजनाएं. निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारियों की जानकारी. अपनी पंचायत में पिल्लिक इंफ्रास्ट्क्यर और नागरिक सेवाओं की जानकारी के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान की जानकारी भी ले सकते हैं।

आंपरेशन सिंदूर सेना के शीर्य और राष्ट्र के स्वाभिमान की गंज

देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना स्वर मुखर किया तब उनकी आवाज में गर्व, शब्दों में साहस और आंखों में भारत के सैनिकों की शौर्यगाथा साफ दिख रही थी। पीएम मोदी द्वारा संसद में दिया गया यह एक भाषण मात्र नहीं था, बल्कि भारत की सैन्य शक्ति, सामर्थ्य, रणनीतिक चतुराई और मानवीय जिम्मेदारी का जयघोष भी था। इसलिए उन्होंने कहा भी. 'मैं भारत का पक्ष रखने

के लिए खड़ा हुआ हूं।" संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष परिचर्चा हुई। लोकसभा में अपने जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेना के सशक्तीकरण का प्रमाण बना है। साथ ही, आतंक और आतंकवाद को देश के शीर्ष नेतृत्व ने न केवल वैश्विक एजेंडा बनाया है बल्कि इसके वित्तपोषक देशों को भी किया है दुनिया भर में बेनकाब...

परेशन सिंदूर से भारत ने दुनिया को दो-टूक संदेश दे दिया है कि वह अमन-शांति का पैरोकार है और युद्ध नहीं चाहता लेकिन आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीते 11 वर्ष में आतंकी ठिकानों पर तीन स्ट्राइक से स्पष्ट है कि भारत के 140 करोड़ नागरिक आतंकवाद को मुहंतोड़ जवाब देने के लिए एकजुटता के साथ खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीयों का मस्तक ऊंचा हुआ है। सेना ने पराक्रम का परिचय दिया। पाकिस्तान और पीओके में की गई कार्रवाई पडोसी देश को



स्पष्ट संदेश भी है कि भारत अपने नागरिकों या भारत की आत्मा पर किए जाने वाले हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा।

यही सार है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद के दोनों सदनों में हुई विशेष परिचर्चा का। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी पर 29 जुलाई को लोकसभा (संसद) में विशेष चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ता और स्पष्टता के साथ भारत का दृष्टिकोण रखा। नए भारत की तीन स्पष्ट नीति को दोहराते हुए उनका कहना था अब भारत अपनी शर्तों पर आतंक का जवाब देगा,

परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा, आतंक के प्रायोजकों और षड्यंत्रकर्ताओं के साथ समान व्यवहार करेगा। उन्होंने बताया कि कैसे भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना के तालमेल ने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के माध्यम से पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और पाकिस्तान के किसी भी लापरवाह कदम का बड़ा और पहले से भी ज्यादा करारा जवाब दिया जाएगा।

संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के विजयोत्सव का सत्र बताया था। विजयोत्सव का अर्थ आतंकी मुख्यालयों को मिट्टी में मिलने का है, सिंदूर की सौगंध पूरा करने का है। यह विजयोत्सव भारत की सेना के शौर्य और सामर्थ्य की विजय गाथा का है, यह विजयोत्सव भारत की 140 करोड़ लोगों की एकता, इच्छा शक्ति और उसके प्रति जीत का है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की जनता के अटूट समर्थन और आशीर्वाद के लिए पीएम मोदी ने आभार व्यक्त करने के साथ उनकी भूमिका की प्रशंसा की। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुई जघन्य आतंकी घटना जिसमें निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर बेरहमी से गोली मार दी गई, पीएम मोदी ने इसे क्रूरता की पराकाष्ठा करार देते हुए कहा कि इसके माध्यम से भारत को हिंसा की आग में झोंकने और सांप्रदायिक अशांति भड़काने की एक सोची-समझी साजिश थी। लेकिन देश की एकजुटता और दृढ़ता से इस साजिश को विफल कर दिया गया।

मारत के मिसाइल उन जगहों तक पहुंचे जहां पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी

भारत ने अतीत में पाकिस्तान के साथ कई युद्ध लड़े हैं लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निर्णायक रूप से निशाना बनाया गया, जिसमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल थे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पीएम मोदी ने बहावलपुर और मुरीदके का विशेष रूप से उल्लेख किया और कहा कि इन ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया, जिससे यह पुष्टि हुई कि भारत के सशस्त्र बलों ने आतंकवादी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान के हवाई ठिकानों को काफी नुकसान हुआ जिनमें से कई अभी भी गंभीर स्थिति में है। पाकिस्तान की परमाणु धमिकयां खोखली साबित हुई और भारत ने दिखा दिया कि परमाणु ब्लैकमेलिंग को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न ही भारत उसके सामने झुकेगा। अब तकनीक संचालित युद्ध का युग है और ऑपरेशन सिंदूर ने इस क्षेत्र में भारत की महारत सिद्ध कर

पहलगाम हमला से ऑपरेशन सिंदूर तक की कहानी...

22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए। मृतकों में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। घटना के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे, घटनास्थल का दौरा किया और रात को ही सुरक्षाबलों और एजेंसियों के साथ बैठ कर निर्देश दिए कि हमले में शामिल आतंकी देश छोड़कर न भाग सके। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 23 और 30 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की बैठक हुई। 23 अप्रैल को सबसे पहले सिंधु जल संधि को स्थिगत करने का निर्णय लिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों का सार्क वीजा निलंबित करने का निर्णय लिया गया। पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत रक्षा. सैन्य और नौसेना के सलाहकारों को अवांछनीय घोषित किया गया। सात मई की रात भारत की सेना ने आतंकियों के साथ-साथ उनके 9 अड्डे को ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 125 से अधिक आतंकवादी मारे गए। सात मई की रात 1 बजकर 22 मिनट पर भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को बताया कि भारत ने केवल आतंकवादियों के ठिकानों और उनके हेडक्वार्टर पर हमला किया है और भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है। ८ मई को पाकिस्तान ने भारत के रिहायशी इलाकों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया। इस हमले में एक गुरुद्धारा को नुकसान पहुंचा, एक मंदिर टूटा और कुछ नागरिक हताहत हुए। इसके बाद अगले दिन भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए उसके 11 एयर बेस को क्षतिग्रस्त कर दिया। भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और उनके आक्रमण करने की क्षमता को पंगु कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था और इसलिए 10 मई को पाकिस्तान के **DGMO** ने भारत के **DGMO** को फोन किया और पांच बजे भारत ने संघर्ष को विराम दिया।

जांच का ढायरा...

जांच की शुरुआत में मृतकों के परिजनों से चर्चा की गई, पर्यटकों, खच्चर वालों, पोनी वालों, फोटोग्राफर और दुकानों में काम करने वाले कुल 1,055 लोग से 3,000 घंटे से भी अधिक समय तक पूछताछ की गई। पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी गई। पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर आतंकियों के स्केच बनाए गए और 22 जून, 2025 को बशीर और परवेज की पहचान की गई। इन्हीं दोनों ने पहलगाम हमले के अगले दिन आतंकियों को शरण दी थी। बशीर और परवेज को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि 21 अप्रैल. 2025 की रात को 8 बजे तीन आतंकी इनके पास आए थे और उनके पास दो एके ४७ और एक एम ४ कार्बाइन राइफल थी। बशीर और परवेज की मां ने भी तीनों मारे गए आतंकियों को पहचान लिया है और एफएसएल से भी इस बात की पुष्टि हो गई है। जांच में स्पष्ट हो गया कि तीनों आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे और इस हमले में इनके पास से मिली 2 एके 47 और एक एम 9 कार्बाइन का उपयोग आतंकी घटना में हुआ था।

दी है। अगर भारत ने पिछले 10 वर्ष तैयारी नहीं की होती तो देश को इस तकनीकी युग में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। पहली बार दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक आत्मनिर्भर भारत की ताकत देखी।

ऑपरेशन सिंदूर पर मिला वैश्विक समर्थन

पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की कार्रवाई को मिले वैश्विक समर्थन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी देश ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने पर आपित्त नहीं जताई। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से केवल तीन देशों ने ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान जारी किए। भारत को दुनिया भर के देशों से व्यापक समर्थन मिला, जिसमें क्वाड और ब्रिक्स जैसे रणनीतिक समूह के साथ-साथ फ्रांस, रूस और जर्मनी जैसे देश भी शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। 10 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत अपनी कार्रवाई बंद करने की घोषणा की थी।



मैं लोकतंत्र के मंदिर में द्वोहराना चाहता हूं-ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने अगर दुस्साहस की कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

ऑपरेशन सिंदूर की पांच बड़ी जीत

पहली जीत

7 मई को ऑपरेशन कर भारतीय सेना ने सिर्फ 22 मिनट में 22 अप्रैल के आतंकी हमले का दिया मुंहतोड़ जवाब। आतंकी ठिकानों और उनके मुख्यालय को किया ध्वस्त।

तीसरी जीत

पाकिस्तान की परमाणु धमकियां भारत के संकल्प के आगे बेअसर रहीं। भारत ने पाकिस्तान की खोखली परमाणु भभकियों की पोल खोली।

पांचलीं जीत

पहली बार, बुनिया ने भारत की आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति को पूरी क्षमता में देखा। 'मेड-इन-इंडिया' ड्रोन और मिसाइलों ने पाकिस्तान की रक्षा संबंधी झूठी कहानी को पूरी तरह से फेल कर दिया।

ढ्सरी जीत

भारत ने सीमाओं से आगे बढ़कर पाकिस्तान के उन इलाकों पर भी वार किया, जहां पहले कभी प्रहार नहीं हुआ था। बहावलपुर और मुरीढ़के तक हमला कर कई आतंकी लांचपैड तबाह किए गए।

चौथी जीत

भारत की तकनीक बनी आतंक के खिलाफ ब्रह्मास्त्र! भारत के हमलों ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान, एयरबेस, रनवे और अन्य ठिकानों को सटीक निशाना बनाया। भारत की अत्याधुनिक तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन किया।

> भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। हम समृद्धि और शांति चाहते हैं और शांति का रास्ता शक्ति से होकर जाता है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



पीएम मोदी ने कहा कि इस घोषणा से तरह-तरह की अटकलें लगाई गईं, जिन्हें उन्होंने सीमा पार से फैलाया जा रहा दुष्प्रचार बताया।

अब हमले के बाद उड़ जाती है षडयंत्रकर्ताओं की नींद

भारत में पहले भी आतंकवादी घटनाएं होती थी लेकिन उनके षडयंत्रकर्ता बेखौफ थे। भविष्य के हमलों की योजना बनाने में जुट जाते थे। अब स्थित बदल गई है। आज हर हमले के बाद षडयंत्रकर्ताओं की नींद उड़ जाती है क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अब जवाबी हमला करेगा। खतरों को सटीकता से खत्म कर देगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने एक 'न्यू नॉर्मल' स्थापित किया है। वैश्विक समुदाय अब भारत के रणनीतिक अभियानों के विशाल पैमाने और पहुंच को देख चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि सिंदूर से सिंधु तक पूरे पाकिस्तान में हमले किए गए। ऑपरेशन सिंदूर ने

एक नया सिद्धांत स्थापित किया है। भारत पर किसी भी आतंकवादी हमले के बाद उसके षड़यंत्रकर्ताओं और पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

भारतीय सेना ने शत-प्रतिशत लक्ष्य किया हासिल

पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय सेना ने एक बार फिर अपने लक्ष्यों को शत-प्रतिशत हासिल किया और देश की ताकत का परिचय दिया। पीएम मोदी ने दोहराया कि भारत के उद्देश्य पहले दिन से ही स्पष्ट थे। भारत का लक्ष्य आतंकवादी नेटवर्क, उनके मास्टरमाइंड और उनके सैन्य केंद्रों को ध्वस्त करना था और यह मिशन योजना के अनुसार पूरा हुआ। भारत का लक्ष्य आतंकवाद का खात्मा है, किसी देश के साथ संघर्ष नहीं। हालांकि जब पाकिस्तान ने आतंकवादियों के समर्थन में युद्ध के मैदान में उतरने का फैसला



ऑपरेशन का उद्देश्य सीमा पार करना या शत्रु क्षेत्र पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान द्वारा वर्षों से पोषित आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। साथ ही सीमा पार से किए गए हमलों में धर्म के आधार पर 26 निर्दोष लोग की हत्या के बाद पीड़ित परिवारों को न्याय ढिलाना था। पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाढ् के प्रशिक्षण का गढ़ है और उसने इसे अपनी राजकीय नीति का आधार बना लिया है। भारत और पाकिस्तान को एक ही समय में आजाढ़ी मिली थी, लेकिन आज भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'लोकतंत्र की जननी' और पाकिस्तान को 'वैश्विक आतंकवाढ़ का जनक' माना जाता है।

-राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

ऑपरेशन महादेव

पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया गया। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में आतंकी सुलेमान उर्फ फैजल जट, हमजा अफगानी और जिब्बान को मौत के घाट उतार दिया। ऑपरेशन महादेव की शुरूआत 22 मई, 2025 को हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन आतंकियों को मारना इतना सरल नहीं था। 22 दिनों तक सीआरपीएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने ड्रोन द्वारा भेजे गए भोजन पर रहकर बेहद कठिन परिस्थितियों में आतंकियों का पीछाकर इन्हें मारा है।



भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया जिसे पाकिस्तान ने अपने ऊपर हमला कान लिया और पूरी ढुनिया से कहने लगा कि उसका आतंकवाढ़ से कोई लेना-ढेना नहीं है। लेकिन जब आतंकवाढ़ियों के जनाजे में पाकिस्तान सेना के अफसर उपस्थित हुए, तब पाकिस्तान पूरी ढुनिया के सामने एक्सपोज हो गया कि वह देरेरिज्म का स्टेट स्पॉन्सर है।

-अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

भारत के लिए ही जीना होगा...

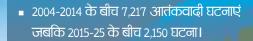
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोढ़ी ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कुछ पंक्तियों का जिक्र किया।

करो चर्चा और इतनी करो, कि ढूश्मन ढ्रशत से ढ्रल उठे, रहे ध्यान बस इतना ही, मान सिंढूर और सेना का प्रश्नों में भी अदल रहे।

हमला मां भारती पर हुआ अगर, तो प्रचंड प्रहार करना होगा, ढुश्मन जहां भी बैठा हो, हमें भारत के लिए ही जीना होगा।



कश्मीर की स्थिति में आए बढ्लाव की कहानी इन आंकड़ों से समझिए...



- 2004-14 के बीच 1,770 नागरिकों की मृत्यू जबिक 2015-25 के बीच संख्या 357 रही।
- 2004-14 के बीच 1,060 सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु जबिक 2015-25 के बीच यह संख्या 542 रही।
- पिछली सरकार में एक साल में 132 दिन तक पाकिस्तान प्रायोजित हडताल के कारण घाटी बंद रहती थी।
- बीते तीन साल में घाटी में एक भी हडताल नहीं हुई है। वैसे ही पत्थरबाजी की भी घटना शून्य हो गई।



किया तो भारत ने एक शक्तिशाली जवाबी हमले से उत्तर दिया। भारत की रक्षा प्रणाली की प्रशंसा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 9 मई को पाकिस्तान द्वारा भारत को निशाना बनाकर लगभग एक हजार मिसाइल और ड्रोन से हमले किए लेकिन भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को तिनके की तरह नष्ट कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने 9 मई की आधी रात और 10 मई की सुबह पाकिस्तान पर इतना जोरदार हमला कि उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ऑपरेशन सिंदुर के अंतर्गत भारत की निर्णायक कार्रवाई ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सीधे भारत को फोन किया और आक्रमण रोकने की विनती की, यह स्वीकार करते हुए कि वे और अधिक हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑपरेशन सिंदुर को फौरी तौर पर रोकने का निर्णय लिया गया।

पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी

पीएम मोदी ने संसद में बताया कि 9 मई की रात, जब वे भारतीय रक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक में थे, तब अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की। कुछ समय बाद उनकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति से फोन पर बात हुई, पीएम मोदी को उन्होंने बताया कि पाकिस्तान एक बड़ा हमला कर सकता है। तब पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया "अगर पाकिस्तान की यही मंशा है, तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।" भारत और भी जोरदार तरीके से जवाबी कार्रवाई करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा "हम गोलियों का जवाब गोलों से देंगे" और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान अब परी तरह से समझ गया है कि भारत की हर प्रतिक्रिया पिछली प्रतिक्रिया से ज्यादा मजबूत होगी। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान ने फिर से दुस्साहस किया तो उसे मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदुर अभी भी सिक्रय और दुढ है।

जिन्होंने दिलाया पिछड़े वर्ग को न्याय

जन्म : 25 अगस्त 1918, मृत्यु : 13 अप्रैल 1982

तारीख...7 अगस्त 1990! कमोबेश सब सामान्य था। उसी दिन शाम को प्रधानमंत्री वीपी सिंह के आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अचानक एक फैसला हुआ। सरकारी फाइलों के बीच करीब दशक भर से धूल फांक रही मंडल आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण को स्वीकार कर लिया गया। जिस आयोग की रिपोर्ट स्वीकार की गई, उसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। मंडल कमीशन के नाम से पहचानी गई उनकी इस रिपोर्ट ने देश की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के तानेबाने को तो फिर से लिखा ही, वंचितों को भी मुख्यधारा से जुड़ने का मिला अधिकार...

हार के मधेपुरा जिले से करीब 15 किमी दूर मुरहो गांव में एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले बीपी मंडल का जन्म 25 अगस्त 1918 को बनारस में हुआ था। जन्म के साथ ही दुश्वारियां भी उनके खाते में आईं। पिता का अगले ही दिन देहांत हो गया। तमाम परेशानियों के बीच शुरुआती पढ़ाई के बाद दरभंगा के हॉस्टल पहुंचे। मुश्किलों ने पीछा यहां भी नहीं छोड़ा। देखा हॉस्टल में अगड़ी जातियों के बच्चों को पहले खाना दिया जाता है। उनका नंबर इनके बाद आता था। कक्षा में आगे की बेंच भी उन्हीं के लिए



3 ढ्शक से ज्याढ़ा समय से लंबित मांग को पूरा कर ओबीसी कमीशन को ढ़ी संवैधानिक मान्यता

काका कालेलकर आयोग के साथ ही मंडल आयोग की सिफारिशों को लंबे समय तक दबाए रखने का जिक़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर 14 दिसंबर 2024 को एक विशेष चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर इतने लंबे समय तक मंडल आयोग की रिपोर्ट को लटकाया नहीं जाता तो आज देश के अनेक पद्धों पर पिछड़े वर्ग के लोग सेवाएं दे रहे होते। बीपी मंडल के विजन को आगे बद़ाते हुए केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग के हित में कई कढ़म उठाए हैं।

- ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की करीब तीन दशक से लंबित मांग को पूरा कर प्रधानमंत्री मोदी ने पिछड़े समाज को उनका अधिकार दिया।
- केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नीट परीक्षाओं में पहली बार 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।
- ओबीसी और ईबीसी के लिए श्रेयस योजना के तहत 2014-15 से 2023-24 तक 38,011 लाभार्थियों के लिए 585.02 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
- ओबीसी समाज के युवाओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति को बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने मेडिकल की सीटों में ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया।





थी। लेकिन, बीपी अब सहन करने की बजाय सामना करने का मन बना चुके थे। हॉस्टल में अपने समूह के लड़के जुटाए और प्रबंधन से भिड़ गए। आखिरकार हॉस्टल प्रबंधन को उनकी बात माननी पड़ी।

पढ़ाई पूरी कर वे मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात हुए, पर भाग्य बीपी को कहीं और पुकार रहा था। वक्त 1952 का था, देश में पहला चुनाव होने जा रहा था, नौकरी छोड़ बीपी मधेपुरा से विधानसभा के चुनावी मैदान में कूद पड़े। पहली ही बार में विधायक भी बने। बीपी के पिता रास बिहारी लाल मंडल ने भी रूढ़ियों एवं भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से बिहार में पिछड़ी जातियों के लिए जनेऊ पहनने की मुहिम चलाई थी। उनके पद चिन्हों पर चलकर बिहार में सामाजिक न्याय के स्वप्नद्रष्टा के तौर पर बीपी पिछड़ा वर्ग के मसीहा बन कर उभरे। राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बीच 1 फरवरी 1968 को राज्य के 7वें मुख्यमंत्री भी बने। हालांकि, उनकी सरकार करीब 50 दिन ही चल पाई। 70 के दशक का वक्त था, देश में सामाजिक भेदभाव के खिलाफ रोष जोरों पर था। आपातकाल के बाद 1977 में मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद संभाला। इसके बाद दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। तय हुआ कि कमीशन का जो अध्यक्ष हो उसकी बड़ी हैसियत होनी चाहिए। ऐसे में पिछड़ा वर्ग के हितों के बड़े हिमायती और उन्हें आरक्षण दिए जाने के बड़े पैरोकार होने के कारण बीपी मंडल को इस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले 1953 में भी पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के लिए कालेलकर आयोग बनाया गया था। हालांकि, उसकी सिफारिशों को कभी लागू नहीं किया गया।

दिसंबर, 1980 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को सौंपी। रिपोर्ट में सभी धर्मों के पिछड़े वर्ग की साढ़े तीन हजार से भी ज्यादा जातियों की पहचान की गई और उन्हें सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की गई। रिपोर्ट सौंपने के करीब 16 महीने बाद ही 13 अप्रैल 1982 को पटना में उनका निधन हो गया। करीब दशक भर दबी रहने के बाद 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। बीपी मंडल नहीं रहे, लेकिन उनकी सिफारिशों ने उन्हें सामाजिक भेदभाव के खिलाफ पिछड़ों की मूक क्रांति का नायक बना दिया।



,,,ताकि भारत वने

alkach am HERIGE

खेल आज भारत के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख माध्यम बन गया है। जब कोई देश खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, तो देश की साख भी बढ़ती है। इसलिए, आज खेल को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार ने बीते 11 वर्ष में परिवर्तनकारी पहल व नीतियों से खेलकूद का आधारस्तंभ खड़ा करते हुए इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ दिया है। जिस देश की 65 फीसदी आबादी 35 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की हो, उसे वैश्विक महाशक्ति बनने से कौन रोक सकता है? इसी सोच को साकार करने के लिए हाल ही में आई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (खेलो भारत नीति-2025), केवल एक नीति नहीं, बल्कि बन गई है महत्वाकांक्षी भारत का दर्शन।

भारत एक बेहतरीन खेल राष्ट्र बने। इसी सोच के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी प्राप्त कर चुकी राष्ट्रीय खेल नित और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के संदर्भ में आइए जानते हैं कि कैसे "खेलेगो-कूदोगे बनोगे लाजवाब" नए भारत की खेल प्रतिभाओं का बन गया है नया मंत्र...

गर देखना है मेरी उड़ान को, थोड़ा और ऊंचा कर दो इस आसमान को। टोक्यो हो या पेरिस ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर एशियन गेम्स अथवा अन्य विश्व स्तरीय खेल प्रतिस्पर्धा, भारत का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों पर यह वाक्य बिल्कुल सटीक बैठता है। भारतीय जैवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा जिम से ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल कर सुनहरा इतिहास रचेंगे, ऐसा सोचा नहीं था। हरियाणा के खंद्रा गांव के किसान सतीश और सरोज देवी के घर 24 दिसंबर 1997 को नीरज का जन्म हुआ। खाने-पीने की वजह से शुरू से ही हट्टे-कट्टे





राष्ट्रीय खेल नीति 2025

मेडल भर नहीं, खेल महाशक्ति के रूप में देश को स्थापित करने का लक्ष्य

- खेल के अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय एथलीटों का प्रदर्शन लंबे समय तक चिंतन का विषय रहा है। कमी थी एक मजबूत स्पोर्ट्स इकोसिस्टम की, जहां जमीनी स्तर से ही प्रतिभाओं को तलाशा और तराशा जाए। इसके साथ ही जरूरी थी दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की, तािक खेलों को करियर के एक बेहतरीन विकल्प के रूप में तैयार किया जा सके।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर वर्ष 2016 से टास्क फोर्स के गठन के साथ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए विशेष शुरुआत हुई।
- खेलो इंडिया, फिट इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और नेशनल टैलेंट सर्च के साथ बेहतरीन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और जमीनी स्तर से ऊपर तक एक इकोसिस्टम तैयार किया गया। नतीजा भारतीय खिलाडियों के प्रदर्शन में भी दिखाई दिया।
- अब इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय खेल नीति 2025 तैयार की गई है। नई नीति, राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। मकसद सिर्फ मेडल जीतना नहीं, बल्कि खेलों को शिक्षा, अर्थव्यवस्था और लैंगिक समानता से जोड़ते हुए भारत को ग्लोबल स्पोर्ट्स पावर के रूप में स्थापित करना है।

नीरज को पिता ने जिम ज्वाइन करा दिया। पानीपत के स्पोर्टस स्टेडियम की जिम ही वो जगह थी जहां नीरज ने पहली बार जैविलन देखा, छुआ और उसे अपने हाथों से बेहतर भविष्य की ओर उछाल दिया। नीरज कहते हैं, "पहली बार जैविलन देखा और फेंका तो उसी वक्त मन में बिठा लिया था कि मुझे ये खेल अपनाना है।" उनके कोच जितेंद्र जगलान भी कहते हैं, "जैविलन थ्रो करवाकर देखा तो मुझे महसूस हुआ कि इसके अंदर कुछ असाधारण योग्यता है।" पानीपत के पास के एक छोटे से गांव से उठकर पूरी दुनिया पर छाने वाले अर्जुन पुरस्कार विजेता नीरज चोपड़ा 140 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक की आशा बने। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल कर उन्होंने इतिहास भी रच दिया।

केवल बेटा ही नहीं, भारत की बेटियों के बढ़ते कदमों को प्रोत्साहित किया जाए तो वह भी विश्व पटल पर देश का नाम रौशन करने की हिम्मत रखती हैं। हरियाणा के झज्जर जिले की गोरिया गांव की रहने वाली मन् भाकर इसी की मिसाल हैं। मनु उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिनकी प्रतिभा को कीर्ति (खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आईडेंटिफिकेशन) के जरिए पहचाना गया। दिल्ली में वर्ष 2018 में आयोजित खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में 15 साल की उम्र में स्वर्ण पदक जीत कर वह चर्चा में आईं। 16 साल की उम्र में मन् आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में दो बार के विजेता को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा भारतीय बनीं। अब 23 साल की मनु भाकर भारतीय खेल जगत की जानी पहचानी खिलाड़ियों में एक प्रमुख चेहरा बन गई हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में दो मेडल जीतकर मनु ने भी इतिहास रच दिया है। दरअसल, ओलंपिक के लिए राष्ट्र का गौरव बनने वाला खिलाड़ी ऐसे ही तैयार नहीं हो जाता है। इन खिलाड़ियों की प्रतिभा, समर्पण, दृढ़ निश्चय और खेल भावना में जब राष्ट्र जुड़ता है, तब जाकर कोई चैंपियन बनता है। खेल की भावना पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्र जीवन में खुलापन के साथ दूसरों को स्वीकार करने का सामर्थ्य देता है। खेल जीवन के अंदर ऐसे गुणों का विकास करता है जो जीवन भर जूझने का सामर्थ्य देता है, खिलाड़ी कभी हार नहीं



मानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी सोच के साथ भारत में अब खेल आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और "खेलेगो-कूदोगे बनोगे लाजवाब" नए भारत की खेल प्रतिभाओं का नया मंत्र बन गया है। पिछला दशक भारतीय खेल इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय रहा है, जिसमें रिकॉर्ड-तोड़ उपलब्धियां और बढ़ती वैश्विक मान्यताएं शामिल हैं। ऐतिहासिक ओलंपिक और पैरालंपिक पदकों से लेकर एथलेटिक्स, बैडिमंटन, कुश्ती और मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन तक, भारतीय एथलीटों ने लगातार लक्ष्य से अधिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। लेकिन यह मंजिल नहीं, बल्कि एक पड़ाव भर है। आकांक्षाओं-उत्साह और सामर्थ्य से भरा भारत अब एक खेल महाशक्ति बनने को संकल्पित हो चुका है। इसी दिशा में हाल ही में 1 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी है जो भारत को वैश्वक खेल महाशक्ति में बदलने का एक स्पष्ट आह्वान है। यह नीति अचानक नहीं लाई गई है, इसके पीछे एक दशक का



किसी भी ढेश की छिव सिर्फ आर्थिक और सैन्य बल से नहीं होती है। ढेश की सौम्य छिव भी उसे एक अलग पहचान ढिलाती है। खेल एक ऐसी सॉफ्ट पावर है जो ढुनिया का ध्यान भारत की ओर आकर्षित करती है।

-नरेंद्र मोढ़ी, प्रधानमंत्री

खेल के विकास की दिशा में

एक सशक्त **कदम**

नई खेल नीति के तहत भारत में खेलों को उत्कृष्टता के साथ जोड़ने की तत्परता का विजन शामिल है तो साथ ही वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों सहित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत की मजबूत दावेदारी और दूरदर्शी रणनीतिक रोड़मैप को भी शामिल किया गया है। इस नीति को 5 मुख्य स्तंभों पर आधारित किया गया है, जो खेलों के हर पहलू को छूते हैं...



1. वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता

- इस नीति का पहला लक्ष्य है, प्रदर्शन और परिणाम में सुधार। इसके लिए खेल विज्ञान, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेनिंग सिस्टम में शामिल किया जा रहा है, ताकि एथलीटों के प्रदर्शन की निगरानी के साथ इसे विश्व स्तरीय बनाया जा सके।
- इसके तहत खेल कार्यक्रमों को जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक मजबूत करने के साथ प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें निखारने के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा।
- नीति के तहत राष्ट्रीय खेल महासंघों की क्षमता और प्रशासन को बेहतर बनाने के साथ-साथ खेल प्रतिस्पर्धा व लीग को बढ़ावा देने के लिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में खेल के ढांचागत विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. आर्थिक विकास

- यह नीति खेलों को एक आर्थिक अवसर के रूप में देखती है। स्पोर्ट्स स्टार्टअप, प्रोफेशनल लीग और स्पोर्ट्स दूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ अंतरराष्ट्रीय आयोजनों को भारत की ओर आकर्षित कर यह नीति खेलों को रोजगार सृजन और आंत्रपेन्योरिशप से जोड़ती है।
- इसके तहत पीपीपी, कॉपीरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और इनोवेटिव वित्तपोषण पहल के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को खेलों के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है।

3. सामाजिक विकास

- यह नित सामाजिक समावेशन पर जोर देती है। महिला एथलीट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जनजातीय समुदाय के युवा वर्ग और दिव्यांगों को मुख्यधारा के खेलों में समान अवसर देने के लिए योजना बनाकर विशेष आयोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर जोर दिया गया है।
- नीति के तहत स्वदेशी व पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ प्रवासी भारतीयों को भी जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

4. जन आंदोलन के रूप में खेल

• खेलों को केवल एलीट वर्ग तक सीमित न रखते हुए, इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। रकूल, कॉलेज, पंचायत और वर्कप्लेस हर स्तर पर खेलों की भागीदारी को संस्कृति का हिस्सा बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी अभियानों और समुदाय-आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से जन भागीदारी व फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ स्कूल, कॉलेज व वर्कप्लेस आदि के लिए फिटनेस सूचकांक शुरू किया जाएगा।

ठोस प्रयास है। यही कारण है कि आज बहुत लोगों को हैरानी होती है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2014 के बाद हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन इतना बेहतर हो गया? आपने देखा है कि भारत ने टोक्यो और पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स में भी भारत ने इतिहास रच दिया। यूनिवर्सिटी गेम्स में भी भारत ने पदकों का नया रिकॉर्ड बनाया। यह अचानक ही नहीं हुआ है। देश के खिलाड़ी की मेहनत और जज्बे में पहले भी कमी नहीं थी लेकिन बीते 11 वर्ष में उसे नया आत्मविश्वास मिला है, कदम-कदम पर सरकार का साथ मिला है। बीते 11 वर्ष में सरकार ने रिफॉर्म किया, खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया और खेल का पूरा तंत्र ट्रांसफॉर्म हो गया। आज खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से देश के हजारों खिलाड़ियों को मदद



5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० के साथ खेलों का एकीकरण

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० के साथ समन्वय में यह नीति शिक्षा और खेल के बीच की खाई को कम करती है। खेलों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। शारीरिक शिक्षा को मजबूत करने और ढोहरे करियर को ओर मजबूत समर्थन दिया जाएगा।
- नर्ड नीति के तहत खेल शिक्षा और जागरूकता को बढावा देने के लिए एजुकेटर और शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित भी किया जाएगा।



खेलों से जुड़े रणनीतिक हांचे पर सरकार का खास फोकस

- राष्ट्रीय खेल नीति २०२५ के तहत भारत में स्पोर्स इकोसिस्टम और इससे जुड़े रणनीति ढांचे के विनियम पर ध्यान दिया गया है।
- इसके अंतर्गत खेल प्रशासन के लिए एक मजबूत नियामक और कानूनी ढांचा स्थापित किया जाएगा तो परिभाषित मानदंडों, प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) और समयबद्ध लक्ष्यों के साथ एक राष्ट्रीय निगरानी ढांचा तैयार किया जाएगा।
- खेल नीति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगी. जो उन्हें राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप अपनी नीतियों को संशोधित करने या तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

दी जा रही है। 2014 में टॉप्स (TOPS) यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को लॉन्च किया था। इसके जरिए टॉप खिलाडियों की ट्रेनिंग, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंच और बड़े खेल आयोजन में भागीदारी सुनिश्चित किया है। अब केंद्र सरकार की नजर 2028 के लॉस एंजेल्स और भविष्य के ओलंपिक गेम्स पर है। इसके लिए भी टॉप्स के तहत खिलाडियों की हर संभव मदद की जा रही है।

भारत की खेल नीतिः एक वैश्विक यात्रा

भारत जब आजाद हुआ, तब प्राथमिकता राष्ट्र निर्माण की थी, जिसमें गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विषयों पर फोकस किया गया, लेकिन खेल विकास को उससे अलग रखा गया। कुछ खेल आयोजन उसके बाद भारत में हुए, लेकिन खेलों का विकास बेहद कम रहा। 1982 में पहली बार खेल को लेकर नीतिगत पहल हुई और खेल विभाग

आवरण कथा



का निर्माण हुआ। उसके बाद 1984 में पहली बार खेल नीति बनी, जिसका उद्देश्य खेल के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना और जन-भागीदारी को बढावा देना था लेकिन. जिस गति से खेल को बढ़ावा मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया। अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष, 1985 के उपलक्ष्य में इसका नाम बदलकर युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग कर दिया गया। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के दौर में यह संभावना बढ़ी कि अब भारत में खेल को लेकर पहल तेज होगी, लेकिन ऐसा जमीनी तौर पर नहीं दिखा। खेल को लेकर परिवर्तनकारी पहल तब हुई, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय 27 मई 2000 को इसे एक अलग मंत्रालय के रुप में स्थापित किया गया। उसका परिणाम हुआ कि बाद के ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अभिनव बिंद्रा, विजेंदर सिंह, मैरीकॉम जैसी सफलताएं भारत को मिलीं। लेकिन, यह भारत जैसे विशाल और सामर्थ्यवान देश के लिहाज से बेहद कम था।

अतीत के अनुभव से सीख लेते हुए भविष्य की रूपरेखा तय करने की दिशा में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य देश के खेल परिदृश्य को नया स्वरूप देना और खेलों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना है। यह नीति जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक खेल कार्यक्रमों को मजबूत करने पर केंद्रित है, जिसमें शुरुआती दौर में प्रतिभाओं की पहचान और मार्गदर्शन करना, प्रतिस्पर्धी लीग एवं प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है। इसका उद्देश्य खेल संघों की क्षमता और संचालन को बढ़ाते हुए, प्रशिक्षण, कोचिंग और समग्र एथलीट सहायता के लिए विश्व स्तरीय प्रणालियों का निर्माण करना है। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 भारत को वैश्वक खेल राष्ट्र के रूप में बदलने के लिए

एक व्यापक रोडमैप प्रदान करती है। हालांकि,

मौजूदा चुनौतियों से पार पाने और 2036 ओलंपिक और उसके बाद भारत को अपना सर्व श्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करने

पारदर्शिता और कामकाज को बेहतर करने की दिशा में भी बड़ा कदम

खेलों में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 23 जुलाई को लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक-2025 पेश किया। बिल में खेल संगठनों के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जिसके कानून बनने के बाद सभी खेल संघों की निगरानी समेत महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं।

कानून बनने के बाद उठाए जाएंगे यह कदम

- भारत में सभी राष्ट्रीय खेल संगठन और क्षेत्रीय खेल निकायों को एक नए कानून के तहत मान्यता लेनी होगी।
- राष्ट्रीय खेल बोर्ड बनेगा जो सभी खेल संगठनों की निगरानी करेगा। यही बोर्ड यह तय करेगा कि किस संगठन को मान्यता मिलेगी और किसकी रह्न होगी।
- खिलाड़ी, कोच और खेल अधिकारियों के लिए नैतिक आचार संहिता बनानी होगी। इससे ढुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।

फायदे... खेलों के लिए नई दिशा और व्यवस्था

- शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में काम करेगा।
- बोर्ड के निर्णयों को ट्रिब्यूनल में चुनौती दी जा सकती है। इसके आदेश नागरिक न्यायालय की तरह बाध्यकारी होंगे। सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान भी होगा।
- खेल संस्थाओं की स्वायता को मान्यता देते हुए जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
- ओलंपिक, पैरालंपिक व अन्य मान्यता प्राप्त खेलों में एक समान शासन प्रणाली स्थापित हो सकेगी।
- प्रत्येक खेल संस्था में आंतरिक आचार संहिता समिति व विवाद निवारण समिति को अनिवार्य बनाया जाएगा।

मान्यता प्राप्त निकायों को आरटीआई (सूचना का अधिकार) के तहत लाकर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए सेफ स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू होगी।



वर्ष 2014 से ऐसे हुई भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार करने की शुरुआत

प्रतिभाएं वहां भी होती हैं, जहां सीधे सरकार की नजर नहीं पहुंच पाती थी। 2014 से केंद्र सरकार के एक नए विजन के साथ भारत में इस पर खास फोकस किया गया। 2016 में लागू की गई 'खेलो इंडिया' के जिए ग्रास रूट लेवल प्रतिभाओं की पहचान और ट्रेनिंग के साथ उन्हें ओलंपिक के मंच तक पहुंचाने की शुरुआत हुई। वहीं, बेहतरीन खेल इंफ्रास्टक्चर के निर्माण के साथ टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स ने भारत में खेलों के एक बेहतरीन ढांचे की बुनियाद रखी। आइए जानते हैं इन योजनाओं ने भारत में कैसे रखी खेलों में व्यापक सुधार की बुनियाद।

खेलो इंडिया...

जमीनी स्तर से ही खिलाड़ियों को नया मुकाम

खेलोगे कूढोगे बनोगे लाजवाब के आदर्श वाक्य के साथ शुरू की गई खेलो इंडिया ने इससे पहले शुरू की गई सभी योजनाओं में कमियों को दूर करने का काम किया। 2017 में इसे 12 कार्यक्षेत्र में बांटकर एक नया रूप दिया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जन भागीदारी और खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। इस योजना को वर्ष 2021 में 3,790.50 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अगले पांच वर्ष के लिए विस्तार दिया गया है।

बदलाव और बेहतरी का माध्यम बनी खेलो इंडिया

3,124.12

करोड़ रु की लागत से 328 नए स्पोर्ट्स इंफ्रास्टक्चर का निर्माण किया गया। इनमें से 238 प्रोजेक्ट का काम पूरा हो गया है। 70

प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और 20 प्रोजेक्ट पर अभी काम शुरू किया जाना है।



17,000

से अधिक मैदानों को जियो टैन किया गया, ताकि इनका भरपूर उपयोग किया जा सके। जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण और सहायता के लिए 1,045 खेलो इंडिया केंद्र (केआईसी) की स्थापना।

जोन वाइज टैलेंट सर्च टीम बनाई गई, ताकि जिला और ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतिभाओं तक पहुंचा जा सके। टैलेंट सर्च पोर्टल की शुरुआत की गई, खिलाड़ी खुढ़ इस पर अपने अचीवमेंट अपलोड़ कर सकते हैं।

34

खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र (केआईएससीई) की अधिसूचना, 306 अकाढमी को मान्यता।

खेलो इंडिया के तहत वार्षिक खेल प्रतियोगिता

- खेलो इंडिया यूथ गेम्स
- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स
- खेलो इंडिया पैरा गेम्स
- खेलो इंडिया विंटर गेम्स राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के रूप में स्थापित

17 संस्करण

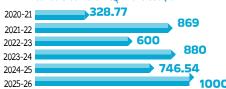
50 हजार से अधिक एथलीटों ने भाग लिया है।

सरकार पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में हर साल खेलो इंडिया नॉर्थ-ईस्ट गेम्स आयोजित करने जा रही है।

2,845

खेलो इंडिया एथलीट को कोचिंग, उपकरण, चिकित्सा देखभाल और मासिक आउट-ऑफ-पॉकेट भत्ते के साथ सहायता दी गुई है। 9-18 वर्ष के बच्चों के लिए खेलो इंडिया उभरती प्रतिभा पहचान (कीर्ति) कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें योग्यता-आधारित प्रतिभा खोज के लिए 174 प्रतिभा मूल्यांकन केंद्रों का उपयोग किया जाता है। कीर्ति का लक्ष्य एथलीटों की एक शृंखला तैयार करना है ताकि भारत को 2036 तक शीर्ष 10 खेल राष्ट्र और 2047 तक शीर्ष 5 में स्थान मिल सके।

खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत आवंटित की गई धनराशि



*नोट : सभी राशि करोड़ रुपये में।



१० साल में लगातार बढ़ा खेलों का बजट

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, केंद्र सरकार ने युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय को रिकॉर्ड 3,794 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2014-15 में 1643 करोड़ रु. आवंटित किए गए थे। इसमें से 2,191 करोड़ रुपये केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए निर्धारित हैं, जबकि 1,000 करोड़ रुपये खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए आवंटित किए गए हैं, जो भारत के खेल भविष्य के निर्माण पर सरकार के विशेष ध्यान को रेखांकित करता है।



के लिए बुनियादी ढांचे, वित्त पोषण, शासन और समावेशिता में सुधार के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है।

देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देने और खेलों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तैयार नई खेल नीति ऐतिहासिक पहल है। खेल नीति पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला- वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, दूसरा- आर्थिक विकास के लिए खेल, तीसरा-सामाजिक विकास के लिए खेल, चौथा- जन आंदोलन के रूप में खेल और पांचवां-नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा के साथ एकीकरण।

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं क्योंकि भारत में खेलों के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के साथ, सरकार ने एक मजबूत खेल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए खेल शिक्षा को प्राथमिकता दी है। सही कहा गया है कि चैंपियन रातों-रात पैदा नहीं होते, बल्कि वे वर्षों के समर्पण, अनुशासन और सबसे महत्वपूर्ण, समर्थन से बनते हैं। परिवारों से मिलने वाला समर्थन, कोच से मिलने वाला समर्थन और सरकार से मिलने वाला समर्थन देश के हर कोने से प्रतिभाओं को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत सरकार अपनी योजनाओं और पहलों के माध्यम से भारतीय एथलीटों को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, खिलाड़ियों को उनके सिक्रय करियर के दौरान और उसके बाद समर्थन देने के साथ-साथ खेल उत्कृष्टता के लिए एक स्थायी इको-सिस्टम बनाना है।

खेल अब बन गई है संस्कृति

प्रधानमंत्री खुद खिलाड़ियों से बात करें। ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा करें और पूछें। क्या भारत में इससे पहले आपने यह सुना था? बीते 11 वर्ष में यह बदलाव आया है भारत की नई खेल संस्कृति में। केंद्र सरकार का काम हर प्रतिभा को जमीनी स्तर से बाहर निकालकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना और इसके लिए हर संभव मदद करना है। इससे पहले लंबे समय तक सिर्फ क्रिकेटर को ही आइकन माना जाता रहा। लोगों की यह मानसिकता बन गई कि क्रिकेट खेलने वाला ही करोड़पति बन पाता है, जबिक अन्य खेलों में मेडल जीतने पर सरकार शुरुआत में तो पैसा देती है, लेकिन उसके बाद ध्यान नहीं दिया जाता। अब यह परिस्थिति बदल रही है। खेल का बेहतरीन इतिहास वाला दुनिया का सबसे युवा देश जहां प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, फिर भी खेल कभी संस्कृति नहीं बन सकी थी। लेकिन, बीते 11 वर्ष में ही केंद्र सरकार ने खेल को संस्कृति बनाकर न केवल खेल की नई परिभाषा गढ़ी, बल्कि यह सोच बन गई है कि खिलाड़ी और एथलीट सिर्फ अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन पर ध्यान लगाएं, बाकी की चिंता देश करेगा। ओलंपिक के जन्मदाता पियरे डी कुबेर्टिन ने कहा था कि खेल में हार-जीत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है खेल में भाग लेना। जबिक प्रधानमंत्री मोदी का सदैव यह मानना रहा है कि खेल में कभी हार नहीं होती। उसमें केवल जीत मिलती है या नई सीख। उत्साह बढ़ाने वाले आधुनिक नेतृत्व की इसी सोच का परिणाम है कि अब समाज खेल को भी एक प्रोफेशन के रूप में स्वीकार कर रहा है। पहले ऐसा कहा जाता था कि खिलाड़ी सरकार के लिए हैं लेकिन अब कहा जाता है कि सरकार पूरी की पूरी खिलाड़ियों के लिए है। जब सरकार और नीतियां बनाने वाले जमीन से जुड़े होते हैं, तब सरकार खिलाड़ियों के हितों के प्रति संवेदनशील होती है, जब सरकार खिलाड़ियों के संघर्ष, उनके सपनों को समझती है, तो इसका

<mark>टॉप्स...ओलंपिक में सफलता के</mark> लिए सबसे बड़ी तैयारी

ओलंपिक में भारतीय एथलीटों के प्रदर्शन में सुधार और उन्हें पूरा समर्थन देने के लिए 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स की शुरुआत की गई थी। इसके तहत केंद्र सरकार भारत के शीर्ष एथलीटों को ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की तैयारी के लिए सहायता देती है। चयनित एथलीटों को मंत्रालय की सामान्य योजनाओं के तहत उपलब्ध नहीं होने वाले प्रशिक्षण और अन्य सहायता के लिए राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) से वित्त पोषण के साथ समर्थन दिया जाता है। कोर ग्रुप एथलीटों को प्रति माह 50,000 रुपये का आउट ऑफ पॉकेट भत्ता (ओपीए) दिया जाता है। इसके अलावा जूनियर एथलीटों को 25,000 रुपये प्रति माह स्कॉलरिंग्प के साथ सहायता देने के लिए एक विकास समूह भी जोड़ा गया। अगस्त 2024 तक, इस योजना के तहत 174 व्यक्तिगत एथलीट और 2 हॉकी टीम (पुरुष और महिला) को कोर ग्रुप के रूप में ग्रुना गया है।

फिट इंडिया मूवमेंट

फिटनेस को बैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने के उद्देश्य से फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस मूवमेंट का मिशन व्यवहार में बदलाव लाना और शारीरिक रूप से अधिक सिक्रय जीवन शैली की ओर बदना है।

योजना की प्रमुख उपलब्धियां...

- अक्टूबर 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत देशभर में 1,500 से अधिक फिट इंडिया प्लॉग रन आयोजित किए गए।
- इस मूवमेंट के तहत, फिट इंडिया फैमिली सेशन आयोजित किए गए,
 जिसका उद्देश्य विशेषज्ञों के साथ फिटनेस पर सरल और आसान सूत्रों के द्वारा परिवारों में फिटनेस रूटीन को शामिल करना था।
- 'फिट इंडिया-स्वस्थ हिंदुस्तान' कार्यक्रम नाम से एक विशेष ऑनलाइन श्रृंखला की शुरुआत की गई जो विख्यात फिटनेस विशेषज्ञों और फिट इंडिया आइकन का एक टॉक शो है।
- पहली बार फिट इंडिया कार्निवल, तीन दिवसीय फिटनेस और वेलनेस फेस्टिवल, मार्च 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया।



खिलाड़ियों के साथ सरकार

खेल में पढ़ार्पण से संन्यास तक थामा हाथ

बीता एक दशक भारत में खेल और खिलाड़ियों के लिए एक स्वर्णिम युग जैसा रहा है। विभिन्न पहल और योजनाओं से जहां सरकार शहरी क्षेत्र से ग्रामीण अंचल तक प्रतिभा की पहचान पोषित कर रही है तो एथलीट की पूरी यात्रा में, हर स्तर पर उनका साथ दिया है। खेलों को बढ़ावा देने के एक व्यापक ढांचे के साथ खिलाड़ियों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा भी की गई है सुनिश्चत...

खेल निध...मेथावी खिलाड़ियों को आजीवन पेंशन

राष्ट्र का परचम फहराने और अपना उत्कृष्ट देने में जुटे खिलाड़ी अक्सर जीवन में शिक्षा और किरयर का त्याग करते हैं। ऐसे में देश को गौरवान्वित करने वाले मेधावी खिलाड़ियों को सरकार खेल निधि से आजीवन पेंशन के साथ आर्थिक सुरक्षा देती है। इसके तहत सिक्रय खेल किरयर से संन्यास लेने के बाद खिलाड़ी को आजीवन 12 हजार रुपये से 20 हजार रुपये तक मासिक पेंशन देती है। ओलंपिक, पैरालंपिक, विश्व कप, विश्व चैंपियनिशप, एशियाई खेल, पैरा एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल में पदक जीतने वाले खिलाड़ी इस पेंशन के पात्र हैं।

आरईपुसईटी...रिटायर खिलाड़ी के लिए फिर से तैयारी का रास्ता

खिलाड़ी जब मैद्धान पर होता है तो सरकार उसके प्रशिक्षण, पोषण और परिवार की जरूरतों के लिए आर्थिक ध्यान रखती है, लेकिन कई मौके ऐसे आते रहे जब रिटायर होने के बाद खिलाड़ी को फिर से खेल से जुड़ने के मौके नहीं मिलते। केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले खिलाड़ियों को फिर से खुद

को साबित करने का मौका देने के लिए 2024 में सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तीकरण प्रशिक्षण (आरईएसईटी) कार्यक्रम की शुरुआत की। यह पहल सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को उनके हिसाब से शिक्षा, इंटर्निशप और कौशल निर्माण का अवसर देती है। इसका लक्ष्य जहां सेवानिवृत्त खिलाड़ियों की रोजगार संबंधी जरूरत की पूर्ति है तो वहीं खेल महाशक्ति के तौर पर उभरते भारत के खेल क्षेत्र में कोविंग, प्रशासन, मेंटरिंग और अन्य क्षेत्रों में

मानव संसाधन की कमी को पूरा करना भी है।

ढ़िट्यांग... ताकि कोई प्रतिभा न छुटे

सरकार ने दिखांगों के लिए खेलकूद योजना शुरू की है, जिसमें जमीनी स्तर पर दिखांगों के बीच समावेशी और सहभागी खेलों को बढ़ावा दिया जाता है। यहां से उभरने और उच्च प्रदर्शन करने वाले पैरा-एथलीटों को राष्ट्रीय खेल महासंघों के माध्यम से अलग से सहायता मिलती है।

सीधा प्रभाव सरकार की नीतियों में भी दिखाई देता है। देश में बेहतरीन खिलाड़ी पहले भी थे, लेकिन उन्हें सहयोग करने वाली नीतियां नहीं थीं। अच्छी कोचिंग की व्यवस्था नहीं थी, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरी आर्थिक मदद नहीं थी। बीते 11 वर्ष में देश उस पुरानी सोच और पुरानी व्यवस्था से बाहर निकल गया है। आज देश में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनकी ट्रेनिंग से लेकर यात्रा और फिटनेस एक्सपर्ट से

INDIA

स्पोर्टस से खेल भावना पैढ़ा होती है जो मैढ़ान पर और मैढ़ान से बाहर, ढ़ोनों ही जगह महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोढ़ी अक्सर कहते हैं- जो खेले, वो खिले।



मैदान पर, मैदान के बाहर भी



डीडीयू राष्ट्रीय कल्याण कोष...मुसीबत में सहायता

केंद्र सरकार ने खिलाड़ी या उसके परिवार पर अचानक आई किसी मुसीबत, आघात या उपकरण एवं कार्यक्रम में भागीदारी के लिए पंडित ढीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष बनाया है। इसमें ५ लाख रुपये तक की एकमुश्त अनुग्रह सहायता, 5,000 रुपये की मासिक पेंशन. 10 लाख रुपये तक की चिकित्सा सहायता और प्रशिक्षण या प्रतियोगिताओं के दौरान लगी चोटों के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता खिलाड़ी को दी जाती है। मृतक खिलाड़ियों के परिवार और कोच. रेफरी और फिजियोथेरेपिस्ट जैसे सहायक कर्मियों को भी क्रमशः अधिकतम ५ लाख रुपये और २ लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिल सकती है।

पंचायत युवा क्रीड़ा और रवेल अभियान

ग्रामीण परिवेश हो या दूरदराज के इलाके... निचले स्तर पर खेलों को बढावा देने के लिए पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में गांव और ब्लॉक स्तर पर खेल इंफ्रास्ट्रक्वर के विकास और उपकरण खरीदने व वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण सहायता

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना भी की गई है। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण और एथलीट समर्थन में महत्वपूर्ण कमी को दूर करने के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र से संसाधन जुटाना है।

राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता

राष्ट्रीय खेल महासंघों (एएनएसएफ) को सहायता योजना में एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के मानदंडों में मई, 2025 में संशोधन कर 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने की भारत की आकांक्षा का भी ध्यान रखा गया है। खिलाडियों के उचित पोषण के लिए भत्ते के साथ ही मुख्य राष्ट्रीय कोच का वेतन बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये मासिक और अन्य कोचों का वेतन 3 लाख रुपये मासिक किया गया है।

लेकर ट्रेनर तक करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके लिए खेलो इंडिया से लेकर टॉप्स तक, समग्र सोच और दुष्टिकोण के साथ भारत में खेल को जन आंदोलन बनाने की मुहिम छेड़ दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, "ओलंपिक के मैदानों में भारत की गूंज ताकत के साथ सुनाई देगी, ऐसी व्यवस्था अब खड़ी हुई है। खेल को जीवन का हिस्सा बनाएं, व्यवस्था विकसित करें, परिवार आगे आएं, समाज आगे आएं और भारत खेल की दुनिया में भी अपना नाम रौशन करे।"

खेल से अर्थव्यवस्था को मिल रहा नया आकार

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भारत का दबदबा बढ़ाने के लिए, खेल प्रतिभाओं की पहचान स्कूल के स्तर पर ही करके उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। खेलो इंडिया से लेकर टॉप्स (TOPS) योजना तक, एक पूरा इकोसिस्टम, इसके लिए विकसित किया गया है। आज पूरे देश के हजारों एथलीट इसका लाभ उठा रहे हैं। सरकार का फोकस पारंपरिक के साथ नए खेलों पर भी है। इसलिए ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में

पदक दर पदक बढ़ता गुणा भारत का कद



ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन सुधर रहा है और पदकों की संख्या बढ़ रही है। रियो डी जेनेरिओ 2016 में 117 सदस्यीय दल ने 2 पदक जीते थे तो यह संख्या टोक्यो 2020 में 7 पहुंची और पेरिस 2024 में 6 खिलाड़ियों के मामूली अंतर से चूकने के बावजूद 6 पदक के साथ भारत ने मजबूत प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता तो दो पदक (स्वर्ण और रजत) जीतने वाले पहले भारतीय बने। वहीं, भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने लगातार दो पदक जीतने और मनु भाकर ने एक ओलंपिक में दो पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया।

रियो डी जेनेरिओ		टोक्यो	पेरिस	पेरिस	
एथलीट	L	एथलीट	एथल	ीट	
9107	2020	119	7054	7	
पदक जीते	.,	पदक जीते	ें पदक	जीते	
2		7	6		

60 साल में 20 और 8 में 15 मेडल

ओलंपिक का पहला आयोजन 1896 में हुआ था, लेकिन भारत ने पहली बार 1900 में हिस्सा लिया। तब से लेकर अब तक भारत ने ओलंपिक में कुल 41 मेडल जीते हैं। 1952 से 2012 यानी कि 60 साल में सिर्फ 20 मेडल, जबिक उसके बाद 2016 से 2024 तक के आठ वर्ष में 15 मेडल जीते हैं।

हॉकी ढीम ने 52 साल बाढ़ जीते लगातार ढ़ो ओलंपिक पढ़क

भारतीय हॉकी टीम ने 1972 के म्यूनिख ओलंपिक के बाद पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर पहली बार लगातार दो ओलंपिक (टोक्यो और पेरिस) में पदक जीतने की उपलिख हासिल की। दरअसल, 1960 से 1972 तक भारत ने लगातार 4 मेडल जीते थे।

पैरालंपिक

पैरालंपिक 2024 में भारत 170 देश में 18वें पायदान पर रहा

989

INDIA

भारत के पैरालंपिक खिलाड़ियों ने बीते 11 वर्ष में उपलिख्यियों के नए आकाश को छुआ है। यह पैरा खेलों में भारत की बढ़ती ताकत और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए देश में मजबूत समर्थन को दर्शाता है। रियो 2016 में जहां सिर्फ 19 एथलीट गए और 4 पदक जीते तो वहीं पेरिस 2024 में 84 एथलीटों का दल गया और 29 पदक जीते।

वर्ष-स्थान	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
2012 (लंदन)	0	1,5	0	1 =
2016 (रियो)	2	1	1	4
2020 (टोक्यो)	5	8	6	19
2024 (पेरिस)	7	9	13	29



पुशियाई खेल

भारत में खेल के मजबूत होते इकोसिस्टम का प्रभाव एशियाई खेलों में प्रदर्शन पर भी पड़ा है। 2014 में भारतीय खिलाड़ियों ने 11 स्वर्ण के साथ 57 पढ़क जीते थे तो वहीं 2023 के हांग्जो एशियाई खेलों में अब तक के सबसे बड़े भारतीय ढल ने 28 स्वर्ण के साथ 107 पढ़क जीते।

वर्ष-स्थान	एथलीट	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल पदक
2014-इंचियोन	541	11	9	37	57
2018 -जकार्ता	570	15	24	30	69
2023 -हांग्जो	655	28	38	41	107

पुशियाई पैरा: पुथलीठों ने रचा इतिहास

भारतीय पैरा-एथलीटों ने २०२३ के एशियाई खेलों में रिकॉर्ड पढ़कों के साथ इतिहास बनाया है। एशियाई पैरा खेल २०२३ में २९ स्वर्ण पढ़क सहित कुल १११ पढ़क जीते। इससे पहले भारत ने एशियाई पैरा खेल 2010 में 14 पढ़क, 2014 में 33 और 2018 में 72 पढ़क जीते थे। इन खेलों की शुरुआत के बाढ़ से यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जहां पदक तालिका में भारत पांचवें स्थान पर रहा।

राष्ट्रमंडल खेल

राष्ट्रमंडल खेलों में भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर टॉप 5 में अपनी जगह बरकरार रखे हुए है। ग्लासमां 2014 में 64 पढ़क, गोल्ड कोस्ट 2018 में 66 तो बर्मिंघम २०२२ में ६१ पढ़कों के साथ बेहतर प्रदर्शन की निरंतरता कायम रही।

वर्ष-स्थान	भारतीय एथलीट	पढ्क जीते	
2014 -ठलासगो	215	64	
2018 -गोल्ड कोस्ट	218	66	
2022 -बर्मिंघम	210	61	

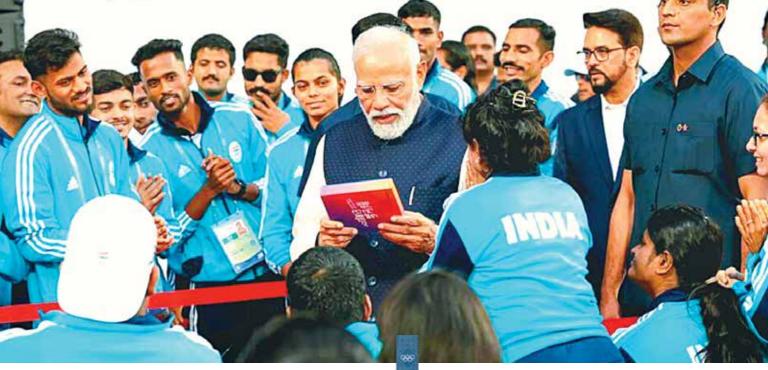
वैश्विक स्तर पर इन उपलब्धियों ने भी बढ़ाया मान

- भारत ने बुडापेस्ट में 2024 एफआईडीए शतरंज ओलंपियाड में दोहरा स्वर्ण पदक जीता।
- भारतीय एथलीटों ने जॉर्डन में 2023 आईटीटीएफ एफए 20 एआई -वातानीपैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 22 पदक जीते।
- भारत ने बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भाला फेंक में स्वर्ण पढक जीता।
- भारतीय बैडिमंटन पुरुष टीम ने मई 2022 में थॉमस कप जीतकर इतिहास रच दिया।
- मिस्र में आयोजित आईएसएसएफ राइफल/पिस्टल विश्व चैंपियनशिप 2022 (सीनियर व जूनियर) में भारतीय दल ने 34 पदक जीते। जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 में भारतीय टीम शीर्ष पर रही।

गतका, कलारीपयट्ट, खो-खो, मल्लखंभ और यहां तक कि योगासन को शामिल किया गया है। वुशु, सेपक-टकरा, पन्चक-सीलाट, लॉन बॉल्स, रोलर स्केटिंग जैसे खेलों में भी अब भारतीय खिलाडी आगे आ रहे हैं। साल 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला टीम ने लॉन बॉल्स में मेडल जीतकर सबका ध्यान आकर्षित किया था। सरकार का जोर, भारत में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर भी है। बीते दशक में खेल के बजट में तीन गुणा से अधिक की वृद्धि की गई है। इस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खेल इंफ्रास्टक्चर पर खर्च हो रहा है। आज देश में एक हजार से अधिक खेलो इंडिया केंद्र चल रहे हैं।

खेल की दिनया और खेल से जड़ी अर्थव्यवस्था केवल खेल के मैदान तक सीमित नहीं है। आज यह नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के भी नए अवसर दे रहा है। इसमें फिजियोथेरेपी, डेटा एनालिटिक्स, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, ब्रॉडकास्टिंग, ई-स्पोर्ट्स, मैनेजमेंट, ऐसे कई सब-सेक्टर शामिल हैं। आज देश के युवा, कोच, फिटनेस ट्रेनर, रिक्रूटमेंट एजेंट, इवेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स लॉयर, खेल मीडिया एक्सपर्ट की राह भी चुन सकते हैं। यानी एक स्टेडियम अब सिर्फ मैच का मैदान नहीं, हजारों रोजगार का स्रोत बन गया है। नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स उद्यम के क्षेत्र में भी अनेक संभावनाएं बन रही हैं। आज देश में जो नेशनल स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी बन रही है या फिर नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है, उसमें खेल को मुख्यधारा की पढ़ाई का हिस्सा बनाया गया है। इसका उद्देश्य भी देश में अच्छे खिलाड़ियों के साथ-साथ बेहतरीन खेल प्रोफेशनल्स बनाने का है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि बीते 11 वर्ष में जिस तरह से खेल को लेकर राष्ट्र-समाज में नया उत्साह पैदा हुआ है, उससे दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने के लक्ष्य में खेल इकोनॉमी की भागीदारी भी बड़ी दिखने लगी है। किसी खेल में केवल एक खिलाड़ी ही नहीं खेलता, उसके पीछे एक पूरा ईको-सिस्टम होता है। कोच, ट्रेनर, न्यदिशन और फिटनेस पर ध्यान देने वाले लोग होते हैं. डॉक्टर होते हैं, उपकरण होते हैं। यानी इसमें सेवा और विनिर्माण दोनों के लिए संभावनाएं होती हैं। आज अलग-अलग खेल का सामान पूरी दुनिया के खिलाड़ी प्रयोग करते हैं, भारत उनका क्वालिटी मैन्युफैक्चरर बन रहा है। उत्तर



प्रदेश के मेरठ में ही खेल का सामान बनाने वाली 35 हजार से ज्यादा छोटी-बड़ी फैक्ट्रियां हैं। इनमें तीन लाख से अधिक लोग काम करते हैं। यही ईको-सिस्टम देश के कोने-कोने में बने, देश इसके लिए काम कर रहा है। टॉप्स योजना के तहत ही देश के दर्जनों खिलाड़ियों पर सैकड़ों करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत देशभर में आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आज स्कूल में भी खेल को मुख्यधारा में शामिल किया गया है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में बन रही है।

खेल बना राष्ट्र-समाज और जीवन का हिस्सा

अगर आज टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाडियों का जीवन संघर्ष प्रेरणा बनी है तो 2028 के लास एंजेल्स ओलंपिक में भारत को शीर्ष 10 देशों की कतार में लाकर खड़ा करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखा गया है। उसकी वजह है केंद्र सरकार की दुरगामी सोच। जब केंद्र में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में कमान संभाली तो गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर अपने अनुभव को आगे बढ़ाते हुए भारत में खेल के बुनियादी ढांचे, खेल सुविधाओं और ओलंपिक में प्रदर्शन को सुधारने के लिए कैसे माहौल दिया जाए, इसकी पहल की। अगस्त 2016 में प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद की बैठक में एलान किया कि 2020, 2024 और 2028 में होने वाले अगले तीन ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की प्रभावी भागीदारी के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार होगी, जिसके लिए एक टास्क फोर्स गठित होगी। इस टास्क फोर्स को खेलकृद के लिए सुविधा, प्रशिक्षण और चयन प्रक्रिया सहित संपूर्ण रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया गया। ओलंपिक के लिए खेल का बजट जो पहले 15-20 करोड़ रुपये हुआ करता था, उसे बढ़ाकर सवा सौ करोड़ रुपये के पार पहुंचाया गया है।

66

हमारा देश विविधतापूर्ण है। हमारे यहां खेलों में हमेशा एक अनूठी शक्ति रही है जो संस्कृतियों, क्षेत्रों और भाषाओं को जोड़ती है।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

खेल से समाज को कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उसी साल 28 अगस्त को अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में देश के लोगों से खेल के लिए माहौल तैयार करने वाले सुझाव देने की अपील की। इस अपील से पहले भी प्रधानमंत्री ने व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए खेल को जीवन का अनिवार्य पहलू बताया। उनका कहना था कि भारत जैसा देश जहां 100 भाषाएं, 1,700 से ज्यादा बोलियां हों, अलग-अलग पहनावे, खान-पान हो वहां एक छोर से दूसरे छोर तक जिला स्तरीय टीम अगर खेलती रहे तो यह राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा आधार बन सकता है।

ओलंपिक मेजबानी का विराट संकल्प

भविष्य में भी भारतीय युवा एथलीट को अंतरराष्ट्रीय मंच मिले और भारत स्पोर्ट्स ईकोसिस्टम का वैश्विक हब बने, इसके लिए भारत संकल्पित है। इसी सोच के साथ वर्तमान केंद्र सरकार 2030 में यूथ

शारीरिक गतिविधियां नहीं बढ़ीं तो पब्लिक हेल्थ पर बढ़ेगा खर्च: डब्ल्यूएचओ

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार वैश्विक स्तर पर 31% वयस्क और 80% किशोर तय मानक के अनुसार फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते।
- डब्ल्यूएचओ ने वर्ष 2025 तक शारीरिक निष्क्रियता के स्तर को 10% और वर्ष 2030 तक 15% कम करने का लक्ष्य रखा है।
- डब्ल्यूएचओ के मुताबिक यदि शारीरिक निष्क्रियता को कम नहीं किया गया तो वर्ष 2020-2030 के बीच करीब 300 बिलियन यूएस डॉलर खर्च पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर होगा।
- वयस्कों में शारीरिक गतिविधियां गैर संचारी रोग को रोकने में मदद करती हैं जिसमें हृदय संबंधी बीमारी, कैंसर, मधूमेह शामिल है। इसके साथ-साथ डिप्रेशन और चिंता में भी कमी आती है।
- बच्चों और किशोर में शारीरिक गतिविधियों की वजह से हड्डियों में मजबूती और मांसपेशियों में विकास होता है।
- नियमित तौर पर व्यायाम और योग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ मिलता है।

ओलंपिक और 2036 में ओलंपिक गेम की मेजबानी की दावेदारी कर रही है। ओलंपिक कभी भारत में आयोजित हों, यह हर भारतीय का सपना रहा है। इतने विराट लक्ष्य के लिए भारत आगे बढ़ रहा है जिसके पीछे बीते 11 वर्ष में खेल को नई संस्कृति बनाने की सफल कोशिश है वहीं, तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने में स्पोर्ट्स इकोनॉमी की भूमिका बढ़ाने की भी है। ओलंपिक केवल एक खेल का आयोजन भर नहीं होता, दुनिया के जिन देशों में भी ओलंपिक होता है, वहां अनेक सेक्टर को गति मिलती है।

ओलंपिक के लिए जो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उससे भी रोजगार बनता है। भविष्य में खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं बनती हैं। जिस शहर में ओलंपिक होता है, वहां नया कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। इससे कंस्ट्रक्शन से जुड़ी इंडस्ट्री को बल मिलता है, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा सेक्टर आगे बढ़ता है। सबसे बड़ा लाभ देश के पर्यटन को मिलता है। अनेकों नए होटल बनते हैं, दुनिया भर से लोग ओलंपिक में हिस्सा लेने और खेल देखने आते हैं। इसका पूरे देश को फायदा होता है। ओलंपिक के आयोजन के लिए भारत की आकांक्षा सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके

पीछे कुछ ठोस कारण हैं। 2036 यानी करीब 11 साल बाद भारत दुनिया में आर्थिक तौर पर और सशक्त होगा। उस समय तक आज के मुकाबले हर भारतीय की आय, कई गुना अधिक होगी। तब तक भारत में एक बहुत बड़ा मध्यम वर्ग होगा। खेल से अंतरिक्ष तक, भारत का तिरंगा और शान से लहरा रहा होगा।

एक अनुमान है कि आने वाले कुछ सालों में ही भारत का खेल उद्योग लगभग एक लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा। इसका सीधा लाभ युवाओं को होगा। बीते वर्षों में खेल को लेकर जो जागरूकता देश में आई है, इससे खेल क्षेत्र से जुड़े व्यापार में तेजी से वृद्धि हो रही है। भारत खेल उपकरणों में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज 300 प्रकार के खेल उपकरण भारत में बन रहे हैं। अब देश के अलग-अलग हिस्सों में खेल उपकरणों से जुड़े क्लस्टर बनाने की तैयारी भी है। आज सिर्फ खेल ही नहीं, हर सेक्टर में भारत का डंका बज रहा है। नया भारत पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करने, नया गढ़ने, नया रचने और नए कीर्तिमान बनाने चल पड़ा है क्योंकि नए भारत को भरोसा है अपने युवाओं के सामर्थ्य पर, उनके जीतने की ललक पर। दृढ़ निश्चय और मानसिक शक्ति पर। आज के भारत में बड़े लक्ष्य तय करने और उसे हासिल करने की क्षमता है। कोई रिकॉर्ड इतना बड़ा नहीं कि उसे तोड़ा न जा सके। भारत अब नए रिकॉर्ड बनाने को संकल्पित है और स्वयं के साथ-साथ दुनिया के लिए नई लकीर खींचने को प्रतिबद्ध। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी युवाओं से आह्वान करते हैं, "आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके साथ भारत आगे बढ़ेगा। जुट जाइए, खुद जीतीए और देश को जिताइए।"

निश्चित तौर से खेल, पूरे देश को एक सूत्र में बांध कर जोश भर देता है और बीते 11 वर्ष में खेल-खिलाडियों को लेकर नई रीति-नीति ने भारत का गौरव भी बढ़ाया है, लोगों का दिल भी जीता है। ऐसे में देश का भी कर्तव्य बनता है कि खुले मन से हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाए। लेकिन यह भी नहीं भूलना होगा कि खेल के क्षेत्र में भारत को विश्व की महत्वपूर्ण शक्ति बनाने की पूरी संभावना युवाओं में है। इसके लिए खेल को न सिर्फ जीवन में महत्व देना होगा बल्कि खेल को अपने समाज में एक संस्कार के रूप में स्थापित करना होगा क्योंकि इस संस्कार के बिना समाज का विकास नहीं हो सकता। राष्ट्र के रूप में केंद्र सरकार नई राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी देकर खेल को समाज और राष्ट्र का जीवन बनाने को प्रयासरत है, ऐसे में आमजन को भी इसे आंदोलन बनाना होगा, ताकि खेल की संस्कृति समाज में रच-बस सके और भारत खेल के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनकर उभरे।



विकास के शिखर की ओर बढ़ता तमिलनाडु

बीते एक दशक में भारत ने मेगा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विकास के नए आयाम छुए हैं तो अपनी विरासत को भी सहेजा है। विरासत भी, विकास भी के इसी मूल मंत्र की झलक 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोढ़ी के तमिलनाडु ढ़ौरे पर दिखाई ढ़ी, जहां 4,800 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर राज्य की विकास यात्रा में एक और अहम पड़ाव को जोड़ा। वहीं, गंगईकोंडा के चोलपुरम मंदिर में तिरूविधरई महोत्सव को संबोधित कर भारत की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत में तमिलनाडु के योगदान को किया नमन...

मिलनाडु ने देश के विकास और विरासत को समृद्ध किया है तो साथ ही यह भारत की समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब भी रहा है। पल्लव, चोल, पांड्य और नायक जैसे विभिन्न राजवंशों के सुशासन ने देश को विकास का मॉडल दिया है। बीते 11 वर्ष में केंद्र सरकार तिमलनाडु में गुड गवनेंस के मॉडल के साथ सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का काम कर रही है। तिमलनाडु में इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर पर केंद्र सरकार लगातार ध्यान दे रही है। बीते एक दशक में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सौगातें राज्य के विकास को लेकर केंद्र

कार्यक्रम में भारत के महानतम सम्राटों में से एक राजेंद्र चोल-। के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया गया।

सरकार की संजीदगी की ही कहानी है। राज्य के विकास की दिशा में केंद्र सरकार की प्राथमिकता की झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा में भी दिखाई दी, जब चार दिन के विदेश दौरे के बाद सीधे तमिलनाडु पहुंचे। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत और ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे फैसले से भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ता है और यह नए आत्मविश्वास का प्रतीक भी है। यही आत्मविश्वास विकसित भारत और विकसित तमिलनाड़ के निर्माण को गति देगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को विकास के शिखर पर लेकर जाने का जो मिशन 2014 में शुरू हुआ था, तूत्कुड़ी लगातार उसका साक्षी बन रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में 'वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट' के लिए 'आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल' का शिलान्यास और सितंबर 2024 में नए तृतुकड़ी अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल के उद्घाटन का उल्लेख कर कहा कि अब जिन नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है उससे राज्य के बुनियादी ढांचे में प्रगति के साथ ही निवासियों का जीवन भी आसान होगा। केंद्र सरकार रेलवे नेटवर्क को औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत की जीवन रेखा मानती है। इसी सोच से रेलवे के बुनियादी ढांचे में बड़े

व्यापक स्तर पर आधुनिकीकरण किया जा रहा है जिसमें तमिलनाडु प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, तमिलनाडु के 77 स्टेशन का व्यापक पुनर्विकास किया जा रहा है। आधुनिक वंदे भारत ट्रेन अब तमिलनाडु के नागरिकों को नया यात्रा अनुभव प्रदान कर रही है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज 'पम्बन ब्रिज' भी तमिलनाड में ही बनाया गया, जो इंजीनियरिंग की अनुठी उपलब्धि है।

विकसित तमिलनाडु के विजन को ध्यान में रखकर पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार यहां के विकास से

इन परियोजनाओं से राज्य के लोगों का जीवन होगा आसान

करोड़ रुपये की लागत से निर्मित तूतुकुड़ी हवाई अइडे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन।

 इस भवन की क्षमता अब सालाना 20 लाख से ज्यादा हवाई यात्री संभालने की हो गई है जो पहले केवल तीन लाख थी। यह क्षमता भविष्य में सालाना २५ लाख की जा सकेगी।



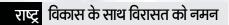
 इसमें तीन बाईपास, कोल्लीडम नदी पर एक किलोमीटर लंबा चार लेन का पुल, चार बड़े पुल, सात फ्लाईओवर और कई अंडरपास शामिल हैं। इसके निर्माण से सेठियाथोप-चोलापुरम के बीच यात्रा समय ४५ मिनट कम हो जाएगा।

- 200 करोड़ रुपये की लागत से 5.16 किमी एनएच-138 तूतुकुड़ी बंदरगाह मार्ग को ६ लेन का बनाया गया। लॉजिस्टिक लागत में कटौती होगी।
- 285 करोड़ रुपये की लागत से वी.ओ. चिढ़ंबरनार बंदरगाह पर 6.96 एमएमटीपीए कार्गो हैंडलिंग क्षमता वाले नॉर्थ कार्गो बर्थ-III का उद्घाटन।
 - दक्षिणी तमिलनाडु में तीन प्रमुख रेलवे इंफ्रास्ट्रक्वर परियोजना का लोकार्पण।
- 550 करोड़ रुपये की लागत वाले विद्युत पारेषण परियोजना-कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई ३ और ४ की आधारशिला रखी गई।



भारत सरकार तमिलनाडु के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रही है। तमिलनाडु में हम पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईटेक बना रहे हैं। साथ ही एयरपोर्ट, हाईवे और रोडवेज को भी आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए, भारत की एकता को प्राथमिकता देनी चाहिए, अपनी नौसेना और रक्षा बलों को मजबूत करना चाहिए, नए अवसर तलाश करने चाहिए और अपने मूल मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। देश इसी दुष्टि से प्रेरित होकर आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

भारत की प्रेरणा

चोलयुग की आर्थिक-सामरिक उन्नति

भारतीय इतिहास के स्वर्णिमयुग में चोल सम्राठों ने देश को सांस्कृतिक एकता में पिरोया था। उन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों को केंद्र सरकार आगे बढ़ाने के लिए काशी-तमिल संगमम् और सौराष्ट्र-तमिल संगमम् जैसे कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में आदि तिरुविधरई महोत्सव को किया संबोधित...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चोल युग में भारत ने जिस आर्थिक और सामिरक उन्नित का शिखर छुआ है, वह आज भी देश की प्रेरणा है। राजराजा चोल ने एक पावरफुल नेवी बनाई थी और राजेंद्र चोल ने इसे और अधिक सुदृढ़ किया था। इतिहासकार चोल काल को भारत के स्वर्णिम युगों में से एक मानते हैं। चोल साम्राज्य ने भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाया। आने वाले समय में तिमलनाडु में राजराजा चोल और उनके पुत्र, प्रख्यात शासक राजेंद्र चोल-I की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी।

पीएम मोदी ने कहा कि विशेष उत्सव राजेंद्र चोल-I के दक्षिण पूर्व एशिया के पौराणिक समुद्री अभियान के 1,000 वर्ष पूरे होने और चोल वास्तुकला के एक शानदार उदाहरण प्रतिष्ठित गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर के निर्माण की शुरुआत का भी स्मरण कराता है। राजेंद्र चोल-I (1014-1044 ई.) इतिहास के सबसे शिक्तशाली शासकों में से एक थे। उनके नेतृत्व में चोल साम्राज्य ने दिक्षण और दिक्षण-पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा कि आज वैश्विक चर्चा अक्सर जल प्रबंधन और पारिस्थितिकी संरक्षण पर केंद्रित होती है, लेकिन भारत के पूर्वजों ने इन मुद्दों के महत्व को बहुत पहले ही समझ लिया था। जहां कई राजाओं को दूसरे क्षेत्रों से सोना, चांदी या पशुधन प्राप्त करने के लिए याद किया जाता है, वहीं राजेंद्र चोल को पवित्र गंगा जल लाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने उत्तर भारत से गंगा जल लाकर दिक्षण में स्थापित किया। पीएम मोदी ने 'गंगा जलमयं जयस्तंभम्' वाक्यांश का उल्लेख कर करते हुए बताया कि जल को चोल गंगा झील में प्रवाहित किया जाता था, जिसे अब पोन्नेरी झील के नाम से जाना जाता है।

जुड़ी नीतियों को लगातार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पिछले ग्यारह वर्ष में, तमिलनाडु को 11 नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं। पहली बार किसी सरकार ने तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन से जुड़े

समुदायों के लिए बड़ी योजना लेकर आई। नीली क्रांति के माध्यम से, सरकार समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए तटीय अर्थव्यवस्था का विस्तार कर रही है।

सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन 57 5 5 5 TETT





हर देश की विकास यात्रा में कुछ ऐसे ऐतिहासिक पल शामिल होते हैं. जो न सिर्फ इतिहास में मील के पत्थर के रूप में याद किए जाते हैं, बल्कि सुनहरे भविष्य की बुनियाद भी बनते हैं। 2014 में नए भारत के निर्माण के साथ शुरू हुई विकास यात्रा में ऐसा ही एक पल १५ अगस्त २०१४ को आया, जब स्वतंत्रता दिवस पर अपने पहले संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के हर परिवार में कम से कम एक बैंक खाते के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की। उद्देश्य था, अंतिम पायदान पर खडे व्यक्ति तक देश के आर्थिक विकास का लाभ पहुंचाना... वित्तीय समावेशन की दुनिया की यह सबसे बड़ी योजना करीब 56 करोड़ बैंक खातों के साथ पूरे कर रही है सफलता के 11 वर्ष...

•जादी के बाद 6 दशक से ज्यादा समय तक देश की 65 फीसदी से अधिक आबादी ऐसी थी, जिनके पास न तो बैंक खाते थे और न बैंकिंग सिस्टम से उनका कोई संबंध। मजबरन यह लोग अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए साहुकारों के चंगुल में फंसते गए। सरकारी योजनाएं तो बनतीं, लेकिन इनका लाभ ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाता। इन्हें देश के विकास की मुख्यधारा में कैसे जोड़ा जाए? इसी सवाल का जवाब बना अंत्योदय का



खाते 23 से 29 अगस्त, 2014 के अभियान में एक सप्ताह में जन धन योजना के तहत खोले गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इसे जगह दी है।

सफलता की कहानी कहते आंकड़े



पीएम जन धन खाता धारकों को सामाजिक सुरक्षा वाली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने के साथ अंशदान का विकल्प दिया जाता है।



विजन। इस विजन को हासिल करने की दिशा में दुनिया की सबसे बड़ी पहल के रूप में 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई। शून्य बैलेंस पर खाता, निःशुल्क रुपे डेबिट कार्ड के साथ एक लाख रुपये की दुर्घटना बीमा जोड़कर इसकी शुरुआत की गई। मकसद स्पष्ट था, गरीब से गरीब नागरिक को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना, ताकि इस वंचित वर्ग की आर्थिक तरक्की की खिड़की खुल सके। दुर्घटना बीमा की राशि को बाद में बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया तो इसके साथ ही खाते पर 10 हजार रुपये तक ओवर ड्राफ्ट की सुविधा भी जोड़ी गई। योजना के तहत करीब 38.5 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए जा चके हैं. जो अमेरिका और कनाड़ा की आबादी से भी अधिक है।

योजना की सफलता के साथ हर परिवार में कम से कम एक बैंक खाते के उद्देश्य से आगे बढ़कर हर वयस्क व्यक्ति के बैंक खाते का लक्ष्य तय किया गया। 11 साल में इस योजना ने करीब 56 करोड़ बैंक खाते खोल कर भारत के साथ-साथ दुनिया में वित्तीय समावेशन की नई गाथा लिखी तो अब केंद्र सरकार की ओर से विकास के लिए भेजा गया हर पैसा पूरा का पूरा सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। विश्व बैंक की ताजा ग्लोबल फिडेक्स डेटाबेस 2025 में कहा गया है कि भारत में 89 फीसदी लोगों के पास बैंक खाते हैं जो 2011 में महज 35 फीसदी के पास थे। यानी बैंक खाता धारक लोगों की संख्या ढाई गुना से भी अधिक हो गई है।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में यह योजना अहम साबित हुई है। अब तक खोले गए कुल बैंक खातों में से 56 फीसदी खाता धारक महिलाएं हैं। करीब-करीब शत प्रतिशत यानी 6 लाख से अधिक गांव को 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग आउललेटस से कवर किया गया है। वंचित परिवार केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न प्रकार की योजना में इस खाते के जरिये आसानी से शामिल हो रहे हैं, उनकी आर्थिक जरूरतें पूरी हों इसलिए सामाजिक सुरक्षा की तमाम योजनाओं को भी इस खाते से जोडा गया है। जन धन बैंक खाते गरीबों के बीच मानसिक बाधा को तोडकर उनके गौरव एवं आत्मसम्मान जगाने का भी काम कर रहे हैं।

डीबीटी से सही लामार्थियों तक पहुंची मदद

जन धन योजना का ही कमाल है कि सदी की सबसे बड़ी आपदा कोविड के समय करोड़ों महिलाओं के बैंक खातों में सरकार ने सीधे 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक रकम ट्रांसफर की। देश में करीब-करीब 10 करोड़ ऐसे फर्जी लाभार्थी थे, जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और उन्हें सरकारी मदद दी जा रही थी, ऐसे लाभार्थियों को सूची से हटाया गया। इस पारदर्शिता से देश का पैसा बच रहा

यूरोपीय यूनियन की कुल आबाढ़ी से ज्याढ़ा भारत में जन धन खाते

55.98

करोड जन धन खाते खोले गए

> **18.62** करोड हैं शहरी क्षेत्र में लाभार्थी

31.21 करोड जन धन खाते महिलाओं के हैं

नोटः आंकड़े करोड़ में, 23 जुलाई 2025 तक

है। जन धन योजना के उन्हीं खातों में आज पीएम-स्विनिधि का पैसा रेहडी-पटरी वाले लोगों को ऋण के रूप में मिल रहा है। अब तक 38 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर(डीबीटी) के जरिए जन धन खातों में भेजी गई है।

जन धन बैंक खातों की सफलता से देशवासी आज परिचित हैं। जब यह योजना आई थी, तो कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा था कि यह खाता खोलना संसाधनों की बर्बादी है, गरीब इनमें एक पैसा भी नहीं डालेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बात केवल पैसे की नहीं थी। बात थी, मानसिक बंधन को तोड़ने की, माइंडसेट बदलने की। जन धन योजना ने गरीब में आत्मविश्वास को जगाया। उसे बैंकों के दरवाजे तक जाने की हिम्मत दी। आज वो बडे अभिमान से अपनी जेब में से रुपे कार्ड निकालता है। बीते 11 वर्ष से गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग, हर कोई अपने जीवन में स्पष्ट बदलाव अनुभव कर रहा है। आज

37.36

करोड़ खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र के बैंकों में खुले

> 38.56 करोड रुपे डेबिट

कार्ड जारी किए गए



अब भी रॉकेट सी रफ्तार

15 दिन में खोले 1.40 लाख जन धन खाते

देश में सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में हर पात्र को लाने के लिए वित्तीय समावेशन की संतृप्ति के तहत 1 जुलाई से अभियान शुरू किया गया। देशभर में ४३ हजार से अधिक शिविर लगाए गए। इसी का नतीजा है कि अभियान के शुरुआती 15 दिन में ही 1.40 लाख जन धन खाते खोले गए। इसके साथ ५.४ लाख से अधिक लोगों ने जन सुरक्षा से जुड़ी तीनों बीमा योजना के तहत नामंकन कराया। 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत लगभग 2.70 लाख ग्राम पंचायत और यूएलबी को कवर किया जा रहा है।



जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों, विशेषकर महिला, युवा और हाशिए पर रहने वाले समुद्धायों को सम्मान देने में सर्वोपरि रही है। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि भ्रष्ट तंत्र तहस-नहस हो गया। इस त्रिशक्ति की वजह से ढाई लाख करोड़ रूपये बचाने का काम हमने किया है।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

देश बहुत व्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ तुष्टिकरण की बजाय संतुष्टिकरण के मार्ग पर चल रहा है। इस दृष्टिकोण ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर दिया है। इस सुरक्षा कवच ने देश के गरीब को और गरीब होने से रोक दिया है।

चाद-मगल सं ओर आगे भारत...

नया भारत 21वीं सद्धी में दुनिया की बड़ी समस्याओं का समाधान करने को आतुर है तो उसकी वजह है- बीते 11 वर्ष में किए गए नीतिगत सुधार और प्रधानमंत्री के स्तर से विज्ञान-तकनीक और वैज्ञानिकों को दिया गया महत्त्व। भारत का अंतरिक्ष सफर अब नई ऊंचाइयां छू रहा है तो इसकी नींव में वह अथक प्रयास है, जिसने इसे रिसर्च के केवल एक क्षेत्र की बजाय राष्ट्रीय मिशन के रूप में हर भारतीय के ढ़िल में स्थापित कर ढ़िया। इस 23 अगस्त को चंद्रयान-३ की सफल लैंडिंग की ढूसरी वर्षगांठ के दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर ढेश के बुलंढ़ इराढ़ों और प्रयासों पर एक नजर...



"अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी को लेकर देश में बहुत चर्चा हुई। जैसे ही शुभांशु धरती पर सुरक्षित उतरे, लोग उछल पड़े, हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा देश गर्व से भर गया। मुझे याद है, जब अगस्त 2023 में चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हुई थी तब देश में एक नया माहौल बना। विज्ञान को लेकर, अंतरिक्ष को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी। अब छोटे-छोटे बच्चे कहते हैं, हम भी अंतरिक्ष में जाएंगे, हम भी चांद पर उतरेंगे - अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनेंगे।"

ह उद्घोष है उस नए भारत का, जिसने अंतरिक्ष के क्षेत्र में नित-नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों के साथ 'मन की बात' कार्यक्रम में इसे साझा किया, जो इस बात का परिचायक है कि 21वीं सदी का भारत आज किस दुष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है और सुधार कर रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में रचते नए इतिहास का आधार बना है- भारत के सामर्थ्य पर अट्ट विश्वास। भारत का सामर्थ्य दुनिया के किसी देश से जरा भी कम नहीं है। इस सामर्थ्य के आगे आने वाली हर रुकावट को दूर करना केंद्र सरकार का दायित्व है, जो वह बखुबी निभा रही है। अंतरिक्ष क्षेत्र और अंतरिक्ष तकनीक को लेकर आज भारत में जो बड़े सुधार हो रहे हैं, वो इसी की एक कडी है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की गौरवपूर्ण मौजूदगी से पहले यह समझना होगा कि असफलता कैसे सफलता को जन्म देती है। जब 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान-2 योजनाबद्ध तरीके से चांद की सतह पर नहीं पहुंच पाया, तब वैज्ञानिक समुदाय में निराशा का भाव दिखा। तब के इसरो प्रमुख के. सिवन की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। ऐसे समय में इसरो कंट्रोल सेंटर में मौजूद देश के नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाकर जो हौसला दिया था, उसका परिणाम देश के सामने है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 न केवल चांद की सतह पर उतरा, बल्कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला भारत, दुनिया का पहला देश बन गया।



भारत के रॉकेट सिर्फ पेलोड नहीं ले जाते. बल्कि 1.4 अरब भारतीयों के सपनों को भी साथ ले जाते हैं। भारत की अंतरिक्ष यात्रा का अर्थ दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना नहीं है। इसका अर्थ है एक साथ मिलकर ऊंचाइयों को छूना। हम मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष की खोज करने के लिए एक साथ मिलकर लक्ष्य साझा करते हैं।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



इसी उपलब्धि के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 23 अगस्त. जिस दिन भारत चंद्रमा पर उतरा. उसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

दरअसल, अंतरिक्ष अनादि काल से हमारी कल्पना को मोहित करता रहा है। ब्रह्मांड की पुकार और हमारी उत्पत्ति के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा अंतरिक्ष के क्षेत्र में शोध की सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति है। इतना सोच भर लेना पर्याप्त नहीं, क्योंकि इस बेहद महंगे और खतरनाक सफर पर सफलता अर्जित करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी जरूरत होती है। जब चंद्रयान-2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, "आज भले ही कुछ रूकावटें आई हों, रूकावटें हाथ लगी हों लेकिन इससे हमारा हौंसला कमजोर नहीं पड़ा है बल्कि और मजबूत हुआ है। आज हमारे रास्ते में भले ही एक आखिरी कदम पर रूकावट आई हो लेकिन इससे हम अपनी मंजिल के रास्ते से डिगे नहीं हैं। उन्होंने उसी दिन यह भी कहा था, "हमारी इच्छाशक्ति और मजबूत हुई है... जब अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात आती है तो इसका सर्वोत्कृष्ट

तरक्की की रफ्तार के साथ सफलताभरा सफर

अंतरिक्ष क्षेत्र में देश अब 2047 के अंतरिक्ष विजन के साथ नई उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है आगे...

उपलब्धियां...जिन्होंने बढ़ाया मान

इसरो ने 2014 से 2025 के बीच 🦰 प्रक्षेपण यान **ँ** मिशन पूरे किए जो 2014 से पहले के 42 मिशनों की तुलना में 38% की वृद्धि है।

मंगलयान

मंगलयान पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला मिशन था। मंगलयान मिशन संभवतः अब तक का सबसे कम खर्चीला अंतरग्रहीय मिशन था. जिसका अनुमानित बजट लगभग 74 मिलियन डॉलर था, जो संसाधनशीलता और इनोवेशन में भारत की विशेषज्ञता का प्रतीक है।



इसरो ने लॉन्च किया अपनी किस्म का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 'निसार'

श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने 30 जुलाई 2025 को नासा के साथ संयुक्त रूप से विकसित नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (NISAR) लांच किया। २३९२ किग्रा वजन वाला निसार दुनिया का पहला ऐसा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो एक ही प्लैटफॉर्म पर बोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक अपर्चर रडार (नासा का L-बैंड और इसरो का S-बैंड) ले गया है। यह पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों की उच्च-रिजॉल्यूशन, सभी मौसम की तस्वीरें उपलब्ध कराएगा। मिशन की लाइफ ५ वर्ष है और अनुमानित लागत 1.5 अरब डॉलर से अधिक है।

398 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए गए

जनवरी 2015 से दिसंबर, 2024 तक पिछले दस वर्ष के दौरान इसरो के पीएसएलवी. एलवीएम३ और एसएसएलवी लॉन्च वाहनों पर वाणिज्यिक आधार पर कुल ३९८ विदेशी उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। यह 2014 से पहले के 35 की तुलना में एक हजार फीसदी से ज्यादा की वृद्धि है।

आना शेष है..." वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आप लोग मक्खन पर लकीर खींचने वाले नहीं, पत्थर पर लकीर खींचने वाले लोग हैं।

आज परिणाम सामने है। शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष में जाना, वहां प्रयोग करना और फिर सकशल वापसी, यह दर्शाता है कि रूकावट के एक दो लम्हों से आपकी उड़ान निर्धारित पथ से बाहर नहीं हो सकती। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुष्टिकोण चार स्तंभों पर आधारित है, जो अपने आप में असाधारण संभावनाओं के द्वार खोलती है-

1. प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी।

- 2. सरकार की भूमिका योग्य बनाने वाले (enabler) के रूप में।
- 3. भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना।
- 4. अंतरिक्ष क्षेत्र को सामान्य मानवी की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना।

एक समय था जब अंतरिक्ष क्षेत्र का मतलब ही होता था सरकार। दशकों तक भारत में स्पेस सेक्टर से जुड़ी प्राइवेट इंडस्ट्री को केवल वेंडर के तौर पर ही देखा गया। सरकार ही सारे अंतरिक्ष मिशन और परियोजनाओं पर काम करती थी। ऐसे में जो सरकारी व्यवस्था में नहीं है, भले ही वो कोई वैज्ञानिक हो या फिर कोई युवा, वो स्पेस सेक्टर से जुड़े अपने आइडियाज पर काम ही नहीं

34 देशों के उपग्रह लॉन्च किए

भारत ने अब तक 34 देशों के उपग्रह लॉन्च किए हैं. जिनमें 2014 से विकसित देशों के उपग्रह भी शामिल हैं।

देश	उपग्रह	
संयुक्त राज्य अमेरिका	232	
यूनाइटेड किंगडम	83	
सिंगापुर	19	\$560 ·
कनाडा	8	•
कोरिया	5	
लक्जमबर्ग	4	
इटली	4	P S
जर्मनी	3	L
बेल्जियम	3	
फिनलैंड	3	
फ्रांस	3	<u>+</u>
स्विट्जरलैंड	2	1
नीदरलैंड	2 /	N D M
जापान	2	I A
इजराइल	2	A .
स्पेन	2	
ऑस्ट्रेलिया	1	E-MEI
संयुक्त अरब अमीरात	1	
ऑस्ट्रिया	1	

अन्य देशों के 8 उपग्रह शामिल हैं।

15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक ही मिशन में एक साथ

उपग्रहों को लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो अब तक नहीं दूटा है।

भारत का पहला सौर मिशन आदित्य एल-1 सितंबर, 2023 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु 1 (एल1) के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना था, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर ढूर है। फरवरी 2025 में आदित्य-एल1 पर लगे सोलर अल्ट्रावॉयलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (एसयुआईटी) ने निचले सौर वायुमंडल, जिनके नाम फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर हैं, में एक शक्तिशाली सौर तीव्र अठिन 'कर्नेल' का अभूतपूर्व दृश्य प्राप्त किया।

OONYX



विक्रम-एस रॉकेट लॉन्च

हैदराबाद के एक स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस ने 18 नवंबर 2022 को इसरो के श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग केंद्र से विकम-एस रॉकेट लॉन्च किया। यह भारत का पहला निजी रॉकेट प्रक्षेपण है।

मिशन शक्ति के तहत एसैट परीक्षण के साथ भारत ने पृथ्वी की निचली कक्षा में दृश्मन के उपग्रहों को नष्ट करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। अब केवल ४ देश (अमेरिका, रूस, चीन, भारत) के पास ही यह क्षमता है।

 जनवरी 2025 में स्पैडेक्स मिशन ने भारत को अंतरिक्ष डॉकिंग में सक्षम चौथा देश बनाया। 2015 में एस्ट्रोसैट की सफलता से मिले डेटा से 400 से अधिक शोध पत्र और 30 थीसिस निकले।

🛮 भारत ने 61 देश और पांच बहुपक्षीय निकायों के साथ अंतरिक्ष सहयोगी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं।

कर पाते थे। इन सबमें नुकसान देश का हो रहा था। ऐसे में स्पेस सेक्टर में सुधार कर, उसे सारी बंदिशों से आजाद कर, इन-स्पेस (IN-SPACE) के माध्यम से प्राइवेट इंडस्ट्री को भी सहयोग कर देश आज विजेता बनाने का अभियान शुरू कर चुका है।

वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति(IN-COPAR) की स्थापना के साथ शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा में 6 दशक में कई अहम पड़ाव आए। लेकिन, बीते 11 वर्ष में इस क्षेत्र ने मजबूत इच्छाशक्ति की बदौलत न केवल सफलता के नए आयाम स्थापित किए, बल्कि अंतरिक्ष कूटनीति के क्षेत्र में भी धाक जमाई है। भारत ने 2014 से लगातार रिफॉर्म्स के साथ इस

क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। पिछले दशक में अंतरिक्ष बजट लगभग तीन गुना बढ़ाया गया है। पिछले दशक में अंतरिक्ष बजट लगभग तीन गुना यानी 2013-14 के 5,615 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2025-26 में 13,416 करोड़ रुपये किया गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में पहली बार 100 फीसदी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनमति दी गई है। वर्ष 2020 में भारत ने इन-स्पेस के रूप में एक नोडल एजेंसी स्थापना कर निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोला। इससे जहां प्रतिस्पर्धा को बढावा मिला तो वहीं इस क्षेत्र में इनोवेशन की नई लहर उठी। नतीजा, हाल के वर्षों में 328 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप उभरे हैं। ये स्टार्टअप इसरो

कदम...जिन पर निर्भर है भविष्य की उड़ान

26 जुन को मिशन एक्सिओम 4 के साथ भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांश शुक्ला अंतरिक्ष में कदम रखने वाले दूसरे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बने। इससे 41 वर्ष पहले विंग कमांडर राकेश शर्मा ने रूसी सोयुज टी-11 के साथ अंतरिक्ष में कदम रखा था।



तक भारतीय अंतरिक्ष मॉड्यूल का लॉन्च।

तक भारत की तैयारी 2040 चालक दल के साथ चंद्रमा पर उतरने की है।



भारत के पहले पूर्ण स्वदेशी मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान कार्यक्रम को लगभग

0,193 करोड़ रुपये

के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। इसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा भेजा जाएगा।





मिशन गगनयान के लिए चार अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग और प्रशिक्षण उड़ानों को पूरा कर लिया गया है। इन चार अंतरिक्ष यात्रियों में ग्रुप कैप्टन पीबी नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगढ़ प्रताप और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु को भारत के मिशन गगनयान के प्रारंभिक चरण के तहत एक्सिओम-४ मिशन पर भेजा गया था।

गगनयान मिशन आगे के और उन्नत मिशनों की आधारशिला रखेगा। इसके बाद वर्ष २०३५ तक भारत खुद के अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की तैयारी कर रहा है।

भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप और निजी क्षेत्र यानी गैर सरकारी कंपनियों की बढ़ावा देने के लिए न सिर्फ नियम आसान किए हैं बल्कि गैर सरकारी कंपनियों के साथ 79 समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर भी किए हैं।

और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर भारत के अंतरिक्ष इनोवेशन इकोसिस्टम का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अंतरिक्ष को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के सरकार के फैसले से भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को भी बढावा मिला है, जिसके 2033 तक वर्तमान 8.4 अरब डॉलर से बढकर 44 अरब डॉलर होने का अनुमान है। नीतिगत दृष्टि के साथ और सुधार करते हुए केंद्र सरकार ने 2023 में नई अंतरिक्ष नीति लागू की है। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना ने अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े उत्पादों की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत किया है। इससे आयात पर निर्भरता कम हुई है और भारत प्रौद्योगिकी निर्यातक के रूप में स्थापित हुआ है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की सफलता की यह कहानी सिर्फ रॉकेट और उपग्रहों से संबंधित नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में आए परिवर्तन की भी है। दरदराज के गांव में खेती करने वाले किसान से लेकर डिजिटल शिक्षा का लाभ उठा रहे छात्रों तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिक अब लोगों के जीवन में शामिल हो चुकी है। भारत की लगातार सफलताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र को आमजन के बीच लोकप्रिय भी बनाया है।

बिहार के संसाधन बिहार की प्रगति



बिहार की जिस पावन भिम ने भारत के स्वाधीनता आंढ्रोलन को सत्याग्रह के रूप में नई दिशा दी थी, अब विकसित भारत के संकल्प पथ को नया आकार दे रही है। सड़क हो या रेल और हवाई यातायात, ऊर्जा हो या निवेश के गंतव्य के साथ राज्य के औद्योगिक व आर्थिक विकास को नई गति ढेने की बात, बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोढ़ी के पूर्वोद्ध्य से भारत उद्धय के विजन में मजबूत कड़ी बनकर उभरा है। बिहार के विकास की इसी गति को और आगे बढ़ाने की कड़ी में पीएम मोढ़ी ने 18 जुलाई को मोतिहारी में आयोजित कार्यक्रम में सौपीं ७ हजार करोड़ रूपये से ज्यादा की सौगातें...

शिवक स्तर पर 21वीं सदी में पश्चिम के प्रभुत्व को पीछे छोड़ पूर्वी देश विकास गाथा में नया योगदान दे रहे हैं तो भारत में भी यह समय पूर्व के राज्यों के उदय का है। 2014 के बाद पूर्वोदय से भारत उदय के इसी विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की रफ्तार में कुछ पीछे रह गए राज्यों पर खास फोकस किया है। अपने इसी दुष्टिकोण का जिक्र पीएम मोदी ने मोतिहारी में आयोजित जनसभा में किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम भारत में मुंबई की तरह मोतिहारी हो, गयाजी में गुरुग्राम की तरह अवसर हों, पटना में पुणे सी औद्योगिक प्रगति हो और संथाल परगना में सुरत की तरह विकास हो, यही केंद्र सरकार का संकल्प है। 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उदघाटन और शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से बीते 10 साल में किए गए प्रयासों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद 10 साल में बिहार में विकास परियोजनाओं के लिए 9 लाख करोड़ रुपये आवंटित



विकास को मिलेगी रफ्तार

- चार नई अमृत ट्रेन की शुरुआत : राजेंद्र नगर टर्मिनल (पटना) से नई दिल्ली, बापूधाम मोतिहारी से दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल), दरभंगा से लखनऊ (गोमती नगर) और मालदा टाउन से लखनऊ (गोमती नगर) के बीच भागलपुर के रास्ते चलेगी यह ट्रेन।
- समस्तीपुर-बछवाड़ा रेल लाइन के बीच स्वचालित सिञ्नलिंग, दरभंगा-थलवारा और समस्तीपुर-रामभद्रपुर रेल लाइन का बोहरीकरण के साथ-साथ 580 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से दरभंगा-समस्तीपूर बोहरीकरण परियोजना की शुरुआत।
- 820 करोड रुपये की लागत वाली एनएच-319 के परारिया से मोहनिया तक ४ लेन, इसके शुरू होने से आरा शहर एनएच-२ (स्वर्णिम चतुर्भुज) से जुड़ गया।
- दरभंगा में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) और पटना में एसटीपीआई की अत्याधुनिक इनक्यूबेशन सुविधा।
- मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपद्धा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत मंजूर मत्स्य विकास परियोजना की श्रृंखला की शुरुआत।

भविष्य की राह होगी आत्पान

- हाइवे-319 पर चार लेन वाले आरा बाईपास, यह आरा-मोहनिया नेशनल हाइवे-३१९ और पटना-बक्सर एनएच-922 को जोडेगा।
- लगभग ४,०८० करोड रुपये की लागत वाली दरभंगा-नरकटियागंज रेल लाइन के दोहरीकरण, पाटलिपुत्र में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, भटनी-छपरा ग्रामीण रेल लाइन (११४ किमी) पर स्वचालित सिञ्नलिंग, भटनी-छपरा ग्रामीण खंड में ट्रैक्शन प्रणाली का उन्नयन।



किए गए हैं, जबकि इससे पहले के 10 साल में यह आंकड़ा केवल 2 लाख करोड रुपये का था।

पीएम मोदी ने कहा कि समाज के आखिरी पायदान के लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचे इसके लिए केंद्र सरकार ने नीतिगत स्तर पर बहुत सुधार किए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। पिछले 11 वर्ष में बिहार में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लगभग 3.5 करोड महिलाओं के बैंक में खाते खोले गए। इसका लाभ यह हुआ कि सरकारी योजनाओं का धन अब सीधे इनके खातों में स्थानांतरित किया जा रहा है। पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के किसानों को लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, जिसमें अकेले मोतिहारी में 5 लाख से ज्यादा किसानों को 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। अब तक 1.5 करोड महिलाओं ने यह उपलब्धि हासिल कर ली है। अकेले बिहार में 20 लाख से अधिक महिला लखपति दीदी बन चुकी हैं और चंपारण में 80 हजार से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर इस मुकाम तक पहुंची हैं। पीएम मोदी ने नारी शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से सामुदायिक निवेश कोष के रूप में 400 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की। यही नहीं, उन्होंने अपने विजन 'बिहार की प्रगति भारत की प्रगति के लिए आवश्यक हैं को दोहराते हुए कहा कि बिहार तभी आगे बढ़ेगा, जब उसके युवा आगे बढ़ेगें।

प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार की आकांक्षा रखने वाले युवाओं की सहायता के लिए हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत







बिहार में न तो क्षमता की कमी है और न ही संसाधनों की और आज बिहार के संसाधन ही उसकी प्रगति के माध्यम बन रहे हैं।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

महत्वपूर्ण योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत किसी निजी कंपनी में पहली नियुक्ति पाने वालों को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। यह योजना 1 अगस्त से लागू होगी और इस पर केंद्र द्वारा एक लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस पहल से बिहार के युवाओं को अत्यधिक लाभ होगा।

बाजारों से जोड कर बढाई जा सकती है आय

बिहार के किसानों की आय बढ़ाने के लिए यूं तो बहुत सारे काम केंद्र और बिहार की सरकार कर रही है. लेकिन अब मखाना की तर्ज पर बिहार में बड़ी मात्रा में पैदा होने वाले केला. लीची, मर्चा और कतरनी चावल, जर्दाल आम, मगही पान जैसे उत्पाद को भी दुनिया भर के बाजारों से जोड़ कर बिहार के किसानों की आय बढाई जा सकती है। साथ ही, बिहार के युवाओं की पहुंच दुनिया भर के बाजार तक पहुंचाई जा सकती है।

अब नौजवान देख रहे बडे सपने

पीएम मोदी ने कहा कि बिहार का एक बड़ा इलाका लंबे समय तक नक्सलवाद से प्रभावित रहा है। इससे यहां के विकास पर असर पड़ा लेकिन, केंद्र सरकार ने नक्सलवाद पर इतना कडा प्रहार किया है कि प्रभावित जिलों में यह अब अंतिम सांस ले रहा है। चंपारण, औरंगाबाद, गयाजी, जमुई जैसे जिले से अब माओवाद का काला साया खत्म हो रहा है और यहां के नौजवान बडे सपने देख रहे हैं।

कई देशों की आबादी से ज्यादा घर बिहार में पीएम आवास योजना के तहत बने

प्रधानमंत्री मोदी ने 12 हजार से ज्यादा परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत घर की चाबी सौंपी। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्ष में पीएम आवास योजना के तहत पूरे देश में 4 करोड़ मकान बनाए जा चुके हैं। इनमें से 60 लाख से ज्यादा घर अकेले बिहार में बनाए गए हैं। यह संख्या दुनिया में नॉर्वे, न्युजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों की कुल आबादी से ज्यादा है। पीएम आवास योजना के तहत देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए जा चुके हैं।

भारत विकास पथ पर आमार बंगाल होबे इंजन



किसी देश की विकास यात्रा सिर्फ कुछ पहलुओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसकी नींव में देश के हर कण-हर नागरिक-हर हिंस्से की बराबर भागीदारी की जरूरत होती है। बीते एक दशक में परिवर्तनकारी बदलावों के साथ भारत जब विकसित राष्ट्र के संकल्प पथ पर आगे बढ़ रहा है तो इस विकास यात्रा में सभी की सिम्मिलित भागीदारी की जरूरत है। पश्चिम बंगाल भी इस कड़ी में अहम साझेदार है। विकसित भारत के लिए विकसित प. बंगाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोढ़ी के इसी विजन की बानगी ढ़िखी 18 जुलाई को ढ़ुर्गापुर में, जहां 5,400 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के साथ उन्होंने राज्य के विकास को ढ़ी और तेज रफ्तार...

रत ने एक दशक की परिवर्तनकारी यात्रा के साथ विकास को नई गति दी है। कनेक्टिविटी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरों के साथ अब गांव और सुदूर अंचल तक केंद्र सरकार की प्राथमिकता हैं। यहां न संसाधनों की कमी है, न इलाकों का भेदभाव, न दुर्गमता कोई वजह है, न विजन में फर्क। सुनियोजित विकास की इस यात्रा में देश का हर राज्य बराबर भागीदार बना है। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य के इसी संकल्प का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प. बंगाल के औद्योगिक शहर दुर्गापुर में आयोजित कार्यक्रम में किया। 5,400 करोड रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उदघाटन व शिलान्यास करते हुए उन्होंने कहा कि इनसे भारत की श्रम शिक्त के इस प्रमुख केंद्र की कनेक्टिविटी और पहचान संशक्त होगी। गैस आधारित परिवहन और गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। यह परियोजनाएं 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द

वर्ल्ड' के दृष्टिकोण के साथ पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ाने में और सहायता करेगी।

पीएम मोदी ने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे का लाभ पश्चिम बंगाल सहित हर राज्य को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल बड़ी संख्या में वंदे भारत रेलगाडियों का संचालन करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है। कोलकाता मेट्टो का भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है। नई रेल पटरियों के दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण पर भी काम चल रहा है। कई रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है तो बड़ी संख्या में रेलवे ओवरब्रिज भी बनाए जा रहे हैं। 18 जुलाई को भी यहां दो और रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया।

'वन नेशन-वन गैस ग्रिड' दुष्टिकोण और प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्ष में. भारत ने गैस कनेक्टिविटी में जबरदस्त प्रगति की है। इस दशक में एलपीजी देश भर में घर-घर तक पहुंच गई है, जिसे



जीवन की गुणवत्ता में होगा सुधार

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गापुर-हिल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के दुर्गापुर से कोलकाता खंड (132 किलोमीटर) राष्ट्र को समर्पित किया। इसे प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के रूप में भी जाना जाता है।
- 390 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पुरुलिया-कोटशिला रेल लाइन (३६ किलोमीटर) के बोहरीकरण का कार्य पूरा।
- जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद के उद्योगों के बीच रांची और कोलकाता के साथ रेल संपर्क में सुधार होगा।
- 380 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पश्चिम बर्धमान के तोपसी और पांडबेश्वर में सेतु भारतम कार्यक्रम के अंतर्गत बने सडक के ऊपर दो पूल (आरओबी) का उद्घाटन।

हमें २०४७ तक भारत को विकसित बनाना है। हमारा रास्ता है -विकास से सशक्तीकरण। रोजगार से आत्मिनिर्भरता और संवेद्धनशीलता से स्शासन। इन्हीं मूल्यों पर चलते हुए हम पश्चिम बंगाल को भारत की विकास यात्रा का मजबूत इंजन बनाकर रहेंगे।

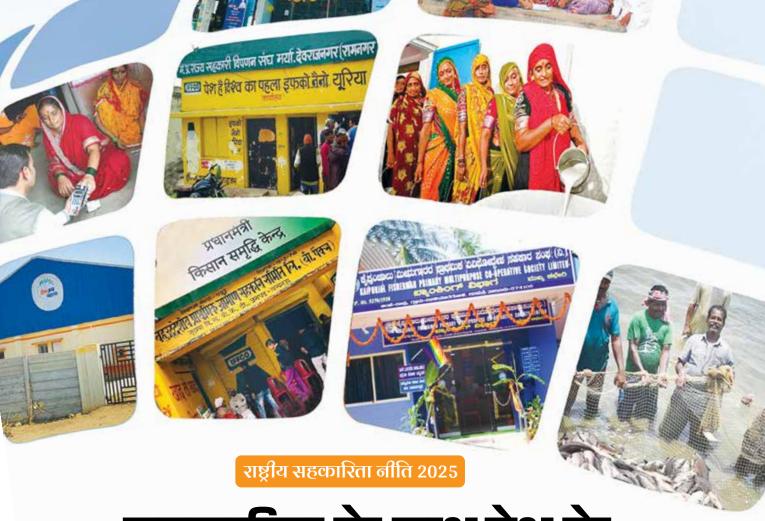
-नरेंद्र मोढ़ी, प्रधानमंत्री

आत्पानी से उपलब्ध होगी सीएनजी और पीएनजी

पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा और पुरुलिया जिले में लगभग 1,950 करोड़ रुपये की लागत से सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी गई। इससे घर, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और औद्योगिक गाहकों को पीएनजी कनेक्शन मिलेगा। साथ ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। प. बंगाल सहित छह पूर्वी राज्यों में गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इससे इन राज्यों में उद्योगों और रसोई तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दुर्गापुर का औद्योगिक क्षेत्र अब राष्ट्रीय गैस ग्रिड का हिस्सा बन गया है। इस परियोजना से क्षेत्र के उद्योगों को लाभ होगा। पश्चिम बंगाल के लगभग 30 लाख घर तक पाइप के माध्यम से सस्ती गैस पहुंचेगी।

दुर्गापुर और रघुनाथपुर में प्रमुख इस्पात और विद्युत संयंत्रों को नई तकनीक के साथ उन्नत किया गया है। इन संयंत्रों में लगभग 1,500 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। यह संयंत्र अब अधिक कुशल और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे भारत के कारखाने हों या खेत, हर प्रयास एक ही संकल्प से प्रेरित है-भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। 💂



सहकारिता के साथ देश के भविष्य को नया आकार

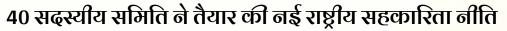
सहकारिता के माध्यम से जब हम अनेक लोगों को जोड़ कर एक प्रबल शक्ति का निर्माण होते हुए देखते हैं, तब पता चलता है कि राष्ट्र निर्माण में छोटे से छोटा व्यक्ति कितना बड़ा योगदान दे सकता है। भारत में करीब 8.25 लाख सहकारी समितियों से जुड़े 30 करोड़ लोगों का आंकड़ा इसकी क्षमता को बताने के लिए काफी हैं। यह समितियां समावेशी विकास के शक्तिशाली इंजन के रूप में उभर रही हैं। सहकार से समृद्धि की इसी मूल परिकल्पना को मजबूती से आगे बढ़ाने की दिशा में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 24 जुलाई को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का किया अनावरण... रत में सहकारिता की क्षमता और इसके विस्तार को ध्यान में रखकर 'सहकार से समृद्धि' विजन के अनुरूप आजादी के 75 वर्ष बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जुलाई, 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। आज देश की छोटी से छोटी सहकारी इकाई का सदस्य भी गर्व और आत्मविश्वास से भरा है। सहकारिता में कंप्यूटरीकरण, नए पैक्स, कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा के साथ जुड़ना और विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को लेकर भारत में सहकारिता की चर्चा है।

केंद्र सरकार द्वारा पायलट परियोजना के तहत 11 राज्यों में 11 पैक्स गोदाम का निर्माण किया जा चुका है, जबिक बाकी 500 से अधिक गोदाम का निर्माण भी दिसंबर, 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। वर्ष 2020 से पहले कुछ लोगों ने सहकारिता को मृतप्राय क्षेत्र घोषित कर दिया था, लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि सहकारिता क्षेत्र एक सुनहरा भविष्य है। बीते 4 साल में सहकारिता क्षेत्र हर पैमाने पर कॉरपोरेट क्षेत्र की तरह समानता

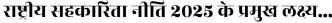
नई सहकारी नीति में सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का समाधान

- सरकार का लक्ष्य देश में एक ऐसा सहकारिता क्षेत्र बनाना है जिसमें युवा अच्छी से अच्छी शिक्षा लेकर कोऑपेरिटिव को अपना करियर बनाएं।
- सहकारिता क्षेत्र की सारी समस्याओं का समाधान नई सहकारी नीति में है। सभी राज्यों ने बिना किसी राजनीतिक मतभेद के मॉडल बायलॉज को स्वीकार किया है।
- अब तक 45 हजार नई पैक्स बनाने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। पैक्स के कंप्यूटरीकरण का काम भी समाप्त हो चुका है।
- पैक्स के साथ जोड़े गए 25 नए काम में से हर काम में कुछ न कुछ प्रगति हुई है।

- पीएम जनऔषधि केंद्र के लिए अब तक 4,108 पैक्स को स्वीकृति मिल चुकी है।
- 393 पैक्स पेट्रोल और डीजल के रिटेल आउटलेट के लिए आवेदन कर चुके हैं। एलपीजी वितरण के लिए 100 से अधिक पैक्स आवेदन कर चुके हैं।
- हर घर नल से जल का प्रबंधन और पीएम सूर्य घर योजना आदि के लिए भी पैक्स काम कर रहे हैं।
- इन सब कामों के लिए प्रशिक्षित मैनपावर के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की नींव डालने का काम भी हो चुका है।



पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व में 40 सब्स्य वाली राष्ट्र स्तरीय समिति ने 750 से अधिक सुझाव, अनेक पक्षों से संवाब, 17 बैठकें, 4 क्षेत्रीय कार्यशाला, आरबीआई तथा नाबार्ड के साथ परामर्श के बाद दूरदर्शी और सहकारिता के अच्छे भविष्य वाली नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति को अंतिम रूप दिया गया है। वर्ष 2002 में पहली बार भारत सरकार सहकारिता नीति लेकर आई थी, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे।



2034

तक सहकारी क्षेत्र के जीडीपी में योगदान को तीन गुना बदाना। 50 करोड़ नागरिकों को सहकारी समिति से जोड़ना।

30% सहकारी समितियों की संख्या में वृद्धि।



- हर तहसील में 5 मॉडल सहकारी गांव विकसित करना।
- सहकारी क्षेत्र का रोजगार सुजन में योगदान।
- सिमितियों में पारदर्शी, वित्तीय स्थायित्व और संस्थागत विश्वास को बढ़ाना।
- श्वेत क्रांति २.० के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना।

सहकारिता को समावेशी, आत्मिनर्भर और भविष्यगामी आर्थिक मॉडल के रूप में विकसित करने वाली राष्ट्रीय सहकारिता नीति, सहकारिता में पारदर्शिता व तकनीकी सशक्तीकरण सुनिश्चित करेगी। इसे नपु क्षेत्रों में विस्तार व रोजगार सृजन का केंद्र बनापुगी। यह नीति पीपुम मोदी की सहकारिता के प्रति गहरी संवेदना और मजबूत इच्छाशिक का प्रमाण है।

- अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

के आधार पर खड़ा है। सहकारिता की इन्हीं क्षमता को मजबूती देने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 जारी गई है।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति - 2025 का अनावरण करते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बने यह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों को साथ रखकर देश के अर्थतंत्र का विकास करने की क्षमता केवल सहकारिता क्षेत्र में है। छोटी-छोटी पूंजी वाले अनेक लोगों को जोड़कर बड़ी पूंजी की व्यवस्था कर उद्यम स्थापित करने की क्षमता भी केवल सहकारी क्षेत्र में है। सहकारी नीति बनाते समय यह ध्यान रखा गया कि इस नीति का केंद्र बिंदु 140 करोड़ लोग हों, गांव, कृषि, ग्रामीण महिलाएं, दिलत और आदिवासी हों। नई सहकारिता नीति से बड़े पैमाने पर रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा होंगे और इस नीति का विजन सहकारिता के माध्यम से समृद्धि लाकर 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है।



आर्थिक विकास की नई साझेदारी का आगाज

मजबूत और निर्णायक नेतृत्व क्षमता, तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग और लोगों की बढ़ती आय के साथ भारत वैश्विक साझेढ़ार के रूप में ढ़ुनिया का सबसे पसंढ़ीढ़ा ढेश बनकर उभरा है। खासतौर पर ऐसे समय में जब ढ़ुनिया के कई ढेश भारी उथलपुथल और टैरिफ वार से जूझ रहे हैं... भारत ने ब्रिटेन के साथ बहुप्रतीक्षित व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता, डबल कंद्रीब्यूशन कन्वेंशन और आपसी साझेढ़ारी के 10 साल के विजन के साथ ऐतिहासिक संबंधों की रखी नई नींव...

📭 ब दो लोकतंत्र और दुनिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच समझौते होते हैं तो वे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढावा देते हैं। विश्व की चौथी बडी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत जहां सबसे तेज आर्थिक रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है तो वहीं मेक इन इंडिया के साथ दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में खुद को विकसित करना चाहता है। अपने इसी लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिवसीय ब्रिटेन दौरे के पहले दिन 24 जुलाई को दोनों देश ने व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समझौते को लेकर कहा कि यह समझौता दो लोकतांत्रिक देशों और विश्व की दो बडी अर्थव्यवस्थाओं के बीच नए विश्वास का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बातचीत में कहा कि इस समझौते से हमारे किसान, एमएसएमई और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे तो टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट, एजुकेशन और पीपल-टू-पीपल कनेक्ट के क्षेत्रों में एक मजबूत, भरोसेमंद और महत्वाकांक्षी साझेदारी का रोडमैप बनेगा।

पीएम मोदी ने सैंड्रिंघम हाउस में किंग चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' पहल के तहत एक खास पौधा गिफ्ट किया। यह पौधा इस बार सर्दी के मौसम में लगाया जाएगा।

भारत-ब्रिटेन विजन २०३५ के साथ भविष्य की साझेदारी का खाका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके के पीएम कीर स्टार्मर ने द्विपक्षीय बैठक में दोनों देश के बीच आपसी साझेदारी के 10 साल के रोडमैप के रूप में भारत-ब्रिटेन विजन 2035 पर भी सहमति जताई। यह ब्लुप्रिंट व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा और विविध बनाने के लिए एक परिवर्तनकारी एजेंडा निर्धारित करता है। यह दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण



किसी विकसित देश के साथ अब तक का सबसे व्यापक समझौता

वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि भारत-ब्रिटेन अभी 56 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार करते हैं। समझौते के बाद 2030 तक यह आंकड़ा दोगुना हो जाएगा। भारतीय कंपनियों को अब ब्रिटेन की सार्वजनिक खरीद प्रणाली में निष्पक्ष और भेदभाव रहित पहुंच मिल सकेगी। यह किसी विकसित देश के साथ भारत का अब तक का सबसे व्यापक समझौता है।

- यूके में 16% तक के टैरिफ अब खत्म होंगे। भारत को 1-2 वर्ष में यूके में 5% से अधिक बाजार हिस्सेदारी मिलने की संभावना। एफटीए से चमडा और फुटवियर निर्यात में 900 मिलियन डॉलर से अधिक की वृद्धि होगी।
- भारत के कृषि उत्पादों को यूके में बेहतर बाजार मिलेगा। 95% से अधिक कृषि टैरिफ लाइनों पर यूके की ओर से टैरिफ जीरो किया जाएगा। इसके अगले ३ वर्ष में २०% से अधिक निर्यात वृद्धि का अनुमान है। भारतीय किसानों के हितों की रक्षा के लिए दूध और खाद्य तेल को इस समझौते से बाहर रखा गया है।
- भारतीय समुद्री उत्पादों पर यूके के टैरिफ समाप्त होंगे। इससे वैश्विक समुद्री निर्यात में भारत की स्थिति और मजबूत होगी।
- भारत के 1,659 इंजीनियरिंग उत्पाद अब शून्य आयात शुल्क के साथ यूके के बाजार में प्रवेश करेंगे। कुल एफटीए कवरेज में 17% हिस्सा इंजीनियरिंग उत्पादों का ही है। समझौते के बाद इस क्षेत्र में 2029-30 तक इन उत्पादों का यूके को निर्यात दोगूना होकर 7.5 अरब डॉलर पहुंचने की संभावना है।
- भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को भी यूके में शून्य शुल्क के साथ प्रवेश मिलेगा। भारत में बने स्मार्टफोन, ऑप्टिकल फाइबर केबल और इन्वर्टर जैसे उत्पादों की यूके के बाजार में पकड़ और मजबूत होगी।
- भारत के मेडिकल डिवाइस निर्यात को भी इस समझौते से नई दिशा मिलेगी। भारतीय जेनेरिक दवाओं के साथ एक्सरे और ईसीजी मशीन जैसे उत्पादों पर यूके में शून्य टैरिफ होगा।
- भारत के रासायनिक निर्यात में 30-40% तक की बढोतरी की संभावना है। वित वर्ष २०२५-२६ में निर्यात ६५०-७५० मिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
- भारत वर्तमान में यूके को ९४१ मिलियन डॉलर मुल्य के रत्न और आभूषण निर्यात करता है, जिसमें से 400 मिलियन डॉलर केवल आभूषण निर्यात से आता है। यूके के लग्जरी और लाइफस्टाइल सेगमेंट में भारत की स्थित और मजबूत होगी। अगले २-३ वर्ष में यह निर्यात दोगुना होने की संभावना है।



भारतीय पेशेवरों को बड़ी राहत

डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के साथ भारतीय पेशेवर और उनके नियोक्ताओं को तीन वर्ष के लिए ब्रिटेन के सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। बता दें कि ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को नेशनल इंश्योरेंस के तौर पर हर साल करीब 500 पाउंड की राशि देनी होती थी। यह भुगतान वहां की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए होता है, लेकिन इसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता, क्योंकि वे कुछ महीनों बाद भारत लौट आते हैं।

व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है और उभरती वैश्विक चुनौतियों के बीच एक सुरक्षित, टिकाऊ और समृद्ध विश्व को बढ़ावा देने के दोनों देशों के साझा संकल्प को दर्शाता है। विजन 2035 के तहत दोनों देश डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, एजुकेशन, डिफेंस के साथ जलवायु व स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में मिलकर काम करेंगे।



भारत=मालदाव... संबंधों में गर्मजोशी का नया अध्याय

भारत और मालढ़ीच केवल पड़ोसी भर नहीं, विकास यात्रा में अनन्य सहयोगी भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोढ़ी की 25-26 जुलाई को ढ़ो ढ़िवसीय मालढ़ीच यात्रा ने इन संबंधों को नई ऊर्जा ही नहीं ढ़ी, बल्कि ढ़ोनों ढ़ेशों के बीच मजबूत संबंधों की एक और बुनियाद रखी। प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ सहयोग और स्थायित्व के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि मालढ़ीच की जनता और सरकार ढ़ोनों को यह भरोसा दिलाया गया कि भारत उनकी प्रगति और सुरक्षा में हमेशा रहेगा साथ....





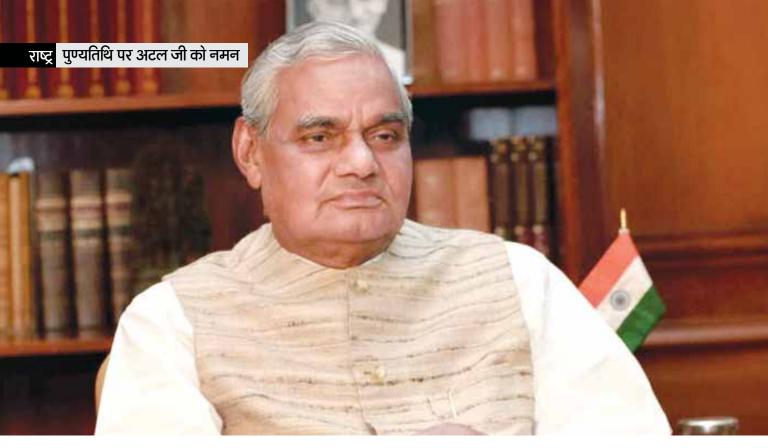
•रत की पड़ोसी प्रथम की नीति में मालदीव का अहम स्थान है तो क्षेत्रीय व समुद्री सहयोगियों के साथ सुरक्षा और विकास के परस्पर तालमेल के तहत महासागर विजन में भी खास सहयोगी है। भारत अपनी इन्हीं प्रतिबद्धता के साथ हर संकट के समय मालदीव के साथ खड़ा नजर आया है। दोनों देशों के रिश्तों की गहराई 25 जुलाई को राजधानी माले में दिखाई दी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन के लिए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू खुद अपनी पूरी कैबिनेट के साथ एयरपोर्ट पहुंचे।

मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्रपति मुइज्जू की भारत यात्रा के दौरान हमने व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी का विजन साझा किया था। अब यह हकीकत बन रहा है। इसी का परिणाम है कि हमारे संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी प्रतिनिधियों के अलावा विपक्षी नेताओं, व्यापारियों, प्रवासियों और छात्रों से भी मुलाकात की। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने हिंद महासागर को मालदीव और भारत के बीच दीर्घकालिक संबंधों का जीवंत प्रमाण बताते हुए कहा है कि दोनों देश के बीच एक अटूट रिश्ता है, जो कूटनीति से कहीं आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में आयोजित एक राजकीय भोज के दौरान मुइज्जू ने भारत सरकार के निरंतर समर्थन और अट्टट दोस्ती के लिए आभार व्यक्त किया।

मुक्त व्यापार समझौते समेत कई मुहों पर बातचीत

- भारत ने मालदीव के वार्षिक ऋण भुगतान दायित्वों को ४० प्रतिशत तक कम करने का भी निर्णय लिया है। इसे 51 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घटाकर २९ मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है। इससे मालदीव को अपनी आर्थिक समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, दोनों देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई।
- विकास परियोजनाओं के क्षेत्र में छह नई परियोजनाओं की शुरुआत की या उन्हें मालदीव को सौंपा गया, जिनमें सामाजिक आवास और सामुदायिक विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।
- विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा ढेते हुए, मत्स्य पालन, मौसम विज्ञान, डिजिटल तकनीक और फार्मा उद्योग में आठ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
- कूटनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी संयुक्त रूप से जारी किया गया। पीएम मोदी ने माले में रक्षा मंत्रालय के नए भवन का उद्घाटन भी किया।
- पीएम मोदी ने मालदीव को 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत एक पौधा गिफ्ट किया। आरोग्य मैत्री पहल के तहत मालढ़ीव को दो भीष्म हेल्थ क्यूब सेट सौंपे गए। भारत सरकार ने मालदीव की सेना को 72 गाड़ियां भी उपहार में दी हैं।





राष्ट्र निर्माण के 'अटल' आदर्श

16 अगस्त 2018, देशवासियों के दिलों के रत्न अढल बिहारी वाजपेयी का निधन एक स्नापन पैदा कर गया था। उनके आदर्शों को आत्मसात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए नव प्रगति और समृद्धि को ध्येय बना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अढल जी की स्मृति में लिखे गए दो ब्लॉग के संपादित अंश के साथ न्यू इंडिया समाचार सिहत कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उनकी सातवीं पुण्यतिथि पर सादर नमन...

मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं... लौटकर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं? आज पूरा देश अपने भारत रत्न अटल को, उस आदर्श विभूति के रूप में याद कर रहा है, जिन्होंने अपनी सौम्यता, सहजता और सहृदयता से करोड़ों भारतीयों के मन में जगह बनाई। पूरा देश उनके योगदान के प्रति कृतज्ञ है। उनकी राजनीति के प्रति कृतार्थ है।

21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए उनकी एनडीए सरकार ने जो कदम उठाए, उसने देश को एक नई दिशा, नई गित दी। 1998 के जिस काल में उन्होंने पीएम पद संभाला, उस दौर में पूरा देश राजनीतिक अस्थिरता से घिरा हुआ था। 9 साल में देश ने चार बार लोकसभा के चुनाव देखे थे। लोगों को शंका थी कि ये सरकार भी उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसे समय में एक सामान्य परिवार से आने वाले अटल जी ने देश को स्थिरता और सुशासन का मॉडल दिया। भारत को नव विकास की गारंटी दी।

वो ऐसे नेता थे, जिनका प्रभाव भी आज तक अटल है। वो भविष्य के भारत के परिकल्पना पुरुष थे। उनकी सरकार ने देश को आईटी, टेलीकम्युनिकेशन और दूरसंचार की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ाया।

एक सामान्य परिवार से आने वाले अटल जी ने न सिर्फ देश को स्थिरता और सुशासन का मॉडल दिया, बल्कि भारत को नव विकास की गारंटी दी।

उनके शासन काल में ही, एनडीए ने टेक्नोलॉजी को सामान्य मानव की पहुंच तक लाने का काम शुरू किया। भारत के दूर-दराज के इलाकों को बड़े शहरों से जोड़ने के सफल प्रयास किये गए। वाजपेयी जी की सरकार में शुरू हुई जिस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने भारत के महानगरों को एक सूत्र में जोड़ा वो आज भी लोगों की स्मृतियों पर अमिट है। लोकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी एनडीए गठबंधन की सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किए। उनके शासन काल में दिल्ली मेट्रो शुरू हुई, जिसका विस्तार आज हमारी सरकार एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में कर रही है। ऐसे ही प्रयासों से उन्होंने न सिर्फ आर्थिक प्रगति को नई शक्ति दी, बल्कि दूर-दराज के क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़कर भारत की एकता को भी सशक्त किया।

जब भी सर्व शिक्षा अभियान की बात होती है, तो अटल जी की सरकार का जिक्र जरूर होता है। शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानने वाले वाजपेयी जी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था, जहां हर व्यक्ति को आधुनिक और गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। वो चाहते थे भारत के वर्ग, यानी ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी और महिला सभी के लिए शिक्षा सहज और सुलभ बने।

उनकी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई बडे आर्थिक सुधार किए। इन सुधारों के कारण भाई-भतीजावाद में फंसी देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। उस दौर की सरकार के समय में जो नीतियां बनीं, उनका मूल उद्देश्य सामान्य मानवी के जीवन को बदलना ही रहा।

उनकी सरकार के कई ऐसे अद्भुत और साहसी उदाहरण हैं, जिन्हें आज भी हम देशवासी गर्व से याद करते है। देश को अब भी 11 मई 1998 का वो गौरव दिवस याद है, एनडीए सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण हुआ। इसे 'ऑपरेशन शक्ति' का नाम दिया गया। इस परीक्षण के बाद दुनियाभर में भारत के वैज्ञानिकों को लेकर चर्चा होने लगी। इस बीच कई देशों ने ख़ुलकर नाराजगी जताई, लेकिन तब की सरकार ने किसी दबाव की परवाह नहीं की। पीछे हटने की जगह 13 मई को न्युक्लियर टेस्ट का एक और धमाका कर दिया गया। 11 मई को हुए परीक्षण ने तो दुनिया को भारत के वैज्ञानिकों की शक्ति से परिचय कराया था। लेकिन 13 मई को हुए परीक्षण ने दुनिया को ये दिखाया कि भारत का नेतृत्व एक ऐसे नेता के हाथ में है, जो एक अलग मिट्टी से बना है। उनके लिए राष्ट्र सर्वोपिर था -बाकी सब का कोई महत्त्व नहीं। इंडिया फर्स्ट -भारत प्रथम, ये मंत्र वाक्य उनका जीवन ध्येय था। पोखरण देश के



लिए जरूरी था तो चिंता नहीं की प्रतिबंधों और आलोचनाओं की, क्योंकि देश प्रथम था। सुपर कंप्यूटर नहीं मिले, क्रायोजेनिक इंजन नहीं मिले तो परवाह नहीं, हम खुद बनाएंगे, हम खुद अपने दम पर अपनी प्रतिभा और वैज्ञानिक कुशलता के बल पर असंभव दिखने वाले कार्य संभव कर दिखाएंगे। और ऐसा किया भी। दुनिया को चिकत किया। सिर्फ एक ताकत उनके भीतर काम करती थी- देश प्रथम की जिद।

उन्होंने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया, ये पुराना भारत नहीं है। पूरी दुनिया जान चुकी थी कि भारत अब दबाव में आने वाला देश नहीं है। इस परमाणु परीक्षण की वजह से देश पर प्रतिबंध भी लगे, लेकिन देश ने सबका मुकाबला किया।

जब भी आप वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के बारे में किसी से बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि वो लोगों को अपनी तरफ खींच लेते थे। उनकी बोलने की कला का कोई सानी नहीं था। कविता और शब्दों में उनका कोई जवाब नहीं था। विरोधी भी वाजपेयी जी के भाषणों के मुरीद थे। युवा सांसदों के लिए वो चर्चाएं सीखने का माध्यम बनतीं। कुछ सांसदों की संख्या लेकर भी, वो कांग्रेस की कुनीतियों का प्रखर विरोध करने में सफल होते। भारतीय राजनीति में वाजपेयी जी ने दिखाया, ईमानदारी और नीतिगत स्पष्टता का अर्थ क्या है।

संसद में कहा गया उनका ये वाक्य... सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी मगर ये देश रहना चाहिए...आज भी मंत्र की तरह हम सबके मन में गूंजता रहता है।

वो भारतीय लोकतंत्र को समझते थे। वो ये भी जानते थे कि लोकतंत्र का



उनका वाक्य... सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी मगर ये देश रहना चाहिए...आज भी मंत्र की तरह हम सबके मन में गूंजता रहता है।

मजबूत रहना कितना जरुरी है। आपातकाल के समय उन्होंने दमनकारी कांग्रेस सरकार का जमकर विरोध किया, यातनाएं झेली। जेल जाकर भी संविधान के हित का संकल्प दोहराया। एनडीए की स्थापना के साथ उन्होंने गठबंधन की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित किया। वो अनेक दलों को साथ लाए और एनडीए को विकास, देश की प्रगति और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधि बनाया।

पीएम पद पर रहते हुए उन्होंने विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब हमेशा बेहतरीन तरीके से दिया। वो ज्यादातर समय विपक्षी दल में रहे, लेकिन नीतियों का विरोध तर्कों और शब्दों से किया। एक समय उन्हें कांग्रेस ने गद्दार तक कह दिया था, उसके बाद भी उन्होंने कभी असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया।

उन में सत्ता की लालसा नहीं थी। 1996 में उन्होंने जोड़-तोड़ की राजनीति न चुनकर, इस्तीफा देने का रास्ता चुन लिया। राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण 1999 में उन्हें सिर्फ एक वोट के अंतर के कारण पद से इस्तीफा देना पड़ा। कई लोगों ने उनसे इस तरह की अनैतिक राजनीति को चुनौती देने के लिए कहा, लेकिन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी शुचिता की राजनीति पर चले। अगले चुनाव में उन्होंने मजबूत जनादेश के साथ वापसी की।

हम सब जानते हैं, अटल जी को भारतीय संस्कृति से भी बहुत लगाव था। भारत के विदेश मंत्री बनने के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देने का अवसर आया, तो उन्होंने अपनी हिंदी से पूरे देश को खुद से जोड़ा। पहली बार किसी ने हिंदी में संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात कही। उन्होंने भारत की विरासत को विश्व पटल पर रखा। उन्होंने सामान्य भारतीय की भाषा को संयुक्त राष्ट्र के मंच तक पहुंचाया।

राजनीतिक जीवन में होने के बाद भी, वो साहित्य और अभिव्यक्ति से जुड़े रहे। वो एक ऐसे किव और लेखक थे, जिनके शब्द हर विपरीत स्थित में व्यक्ति को आशा और नव सृजन की प्रेरणा देते थे। वो हर उम्र के भारतीय के प्रिय थे। हर वर्ग के अपने थे। अटल जी कभी लीक पर नहीं चले। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में नए रास्ते बनाए और तय किए। "आंधियों में भी दीये जलाने" की क्षमता उनमें थी। पूरी बेबाकी से वे जो कुछ भी बोलते थे, सीधा जनमानस के हृदय में उतर जाता था। अपनी बात को कैसे रखना है, कितना कहना है और कितना अनकहा छोड़ देना है, इसमें उन्हें महारत हासिल थी।

वे कहते थे-

"हे प्रभु! मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना। गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना"

अपने देशवासियों से इतनी सहजता और सरलता से जुड़े रहने की यह कामना ही उनको सामाजिक जीवन के एक अलग पायदान पर खड़ा करती है। अपने पुरुषार्थ को, अपनी कर्तव्यनिष्ठा को राष्ट्र के लिए समर्पित करना उनके व्यक्तित्व की महानता को प्रतिबिंबित करता है। देश के साधनों, संसाधनों पर पूरा भरोसा करते हुए, हमें अटल जी के सपनों को पूरा करना है, उनके सपनों का भारत बनाना है। मुझे विश्वास है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिखाए सिद्धांत ऐसे ही, हमें भारत को नव प्रगति और समृद्धि के पथ पर प्रशस्त करनें की प्रेरणा देते रहेंगे।

(अटल जी के निधन और जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखे गए दो ब्लॉग का संपादित अंश)

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय

सहकारी समितियां होंगी और सशक्त

रेलवे के 4 मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट को भी मंज़री

किसान केंद्र सरकार की प्राथमिकता हैं तो आधुनिक बुनियादी ढांचे की मजबूती सबसे बड़ा लक्ष्य। इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 31 जुलाई को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 6 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। इनके तहत जहां सहकारी समितियों को और मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को करोड़ों रुपये दिए जाएंगे तो वहीं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत कृषि से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही रेलवे के चार मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी से मिलेगी रेल नेटवर्क को नई रफ्तार...

निर्णय : राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को चार साल में 2.000 करोड रूपये का केंद्रीय अनुदान।

प्रभाव : सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक उत्थान, आधारभूत ढांचे विकसित करने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश में मौजूद 8.25 लाख से अधिक सहकारी समितियों में करीब 30 करोड़ सदस्य हैं, जिनमें 94% संख्या किसानों की है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सरकार की ओर से जारी अनुदान के तहत चार साल (2025-26 से 2028-29 तक) तक सालाना 500 करोड रुपये दिए जाएंगे। निगम इस दौरान खुले बाजार से 20,000 करोड़ रुपये भी जूटा सकेगा।

सरकार की ओर से दिया गया फंड निगम की ओर से ऋण के रूप में सहकारी संस्थाओं को नए प्रोजेक्ट शुरू करने, प्लांट का विस्तार करने और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाएगा। इस फैसले से डेयरी, पशुधन, मत्स्य पालन, चीनी, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और शीतगृह जैसे विभिन्न क्षेत्रों की 13,288 सहकारी समिति. श्रमिक एवं महिलाओं के नेतृत्व वाली समितियों के लगभग 2 करोड़ ९० लाख सदस्य लाभान्वित होंगे।

देश की सहकारी समितियों को सशक्त करने के लिए हमने एक अहम कढ्म उठाया है। इसके तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के लिए 2,000 करोड़ रूपये की केंद्रीय अनुदान सहायता योजना को मंजूरी ढ़ी गई है। इससे डेयरी और

भंडारण जैसे क्षेत्रों को काफी लाभ होने वाला है।

- नरेंढ मोढी. प्रधानमंत्री

निर्णय : किसान संपद्धा योजना के लिए 1,920 करोड़ के अतिरिक्त रवर्च सहित ६,520 करोड़ रू. के बजट को मंजूरी।

प्रभाव : बजट मंजूरी के साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट और एनएबीएल से मान्यता प्राप्त 100 फूड टेस्टिंग लैब की स्थापना के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्वर को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी और दुर्गम क्षेत्र सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रस्तावित ५० इरेडिएशन युनिट के कार्यान्वयन से प्रति वर्ष २० से 30 लाख मीट्रिक टन तक अन्न संरक्षण की क्षमता विकसित होने की उम्मीद है। इरेडिएशन युनिट से कटाई के बाद फसल के नुकसान को कम करने, सूक्ष्मजीवों के संक्रमण को रोकने और खाद्य उत्पादों को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने में मदद मिलती है।

निर्णय : महाराष्ट्र, एमपी, प. बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड के 13 जिलों से जुड़ी 4 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं मंजूर।

प्रभाव : लगभग ११,१६९ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली ये परियोजनाएं वर्ष २०२८-२९ तक पूरी होंगी। इनसे लगभग २२९ लाख मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार भी सुजित होगा। इन परियोजनाओं में इटारसी - नागपूर चौथी लाइन, औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर) - परभणी दोहरीकरण, अलुआबारी रोड- न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन, डांगोपोसी- जारोली तीसरी और चौथी लाइन शामिल हैं। इससे रेल नेटवर्क में 574 किमी की वृद्धि हो जाएगी। प्रस्तावित मल्टीट्रैकिंग परियोजना लगभग 2,309 गांव तक कनेविटविटी बढ़ाएगी, जिनकी जनसंख्या लगभग ४३.६० लाख है।

71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

शाहरुख खान, विक्रांत मैसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, रानी मुखर्जी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री

भारत में सिनेमाई उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए 1954 में शुरू किए गए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ने न केवल प्रतिभा को पहचान दी है, बल्कि राष्ट्र की सांस्कृतिक छिव को आकार देने वाली विविध संस्कृतियों और कहानियों को भी आगे बढ़ाया है। 1 अगस्त को 71 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इसमें जहां 'जवान' फिल्म के लिए शाहरूख खान और '12 वीं फेल' फिल्म के लिए विक्रांत मैसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया वहीं 'मिसेज चढ़ जी वर्सस नॉर्व' फिल्म में अभिनय के लिए रानी मुखर्जी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कि गई घोषित...

सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार

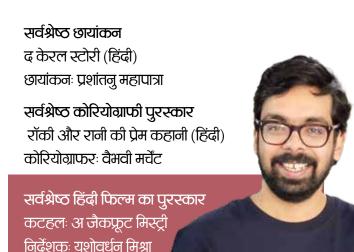




12वीं फेल (हिंदी) अभिनेता विकांत मैसी



सर्वश्रेष्ठ निर्देशनः द केरल स्टोरी (हिंदी), निर्देशकः सुदीप्तो सेन







PMO India 🐡 @PMOIndia

हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। हमारा रास्ता है-विकास से सशक्तिकरण। रोजगार से आत्मनिर्भरता। और संवेदनशीलता से सुशासन: PM @narendramodi



रक्षा मंत्री कार्यालय/ R... 🤤

6 और 7 मई 2025 को, भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। वह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, उसकी अस्मिता, देश के नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति का एक effective और decisive demonstration था: रक्षा मंत्री श्री @rajnathsingh



Amit Shah 🐡

'ऑपरेशन सिंदर' किसी के कहने पर नहीं रोका गया। पाकिस्तान घटनों के बल आ गया और वहाँ के DGMO ने कॉल करके कहा...'बहत हो गया, अब कृपया इसे रोक दीजिए'।



Nitin Gadkari @ @nitin_gadkari

Bharat celebrates a landmark moment with the signing of the historic #IndiaUKFTA! 25 9 28

Gratitude to the visionary leadership of Hon'ble PM Shri @narendramodi Ji, this milestone pact offers Indian exports duty-free access to the UK, boosting agriculture, pharma, MSMEs, and labour-intensive sectors.



Piyush Goyal 🐡

The India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) is a game-changer.

It is encouraging to witness the optimism of our business leaders and their resolve to leverage the #IndiaUKFTA for growth, collaboration & global competitiveness.



Arjun Ram Meghwal 🦈 @arjunrammeghwal

Operation Sindoor ने Defence Market में भारत का झंडा गाड दिया है। दुनिया में Made in India हथियारों की मांग बढ़ रही है।

#ModiGovtAgainstTerror

मालदीव को पांच हजार करोड़ की मदद,

वीन की सकिय स्टब्सिसिसी

इपने के लिए भारत ने खेला अपना पिटारा

मालदीव से तमिलनाडु के तूतीकोरिन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी एफटीए पर होगी बात, यूपीआइ पर संधि 4800 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण मोदी बोले, 'एक पेड़ मां के नाम कनेक्टिविटी, रसद दक्षता व ऊर्जा ढांचे होंगे बेहतर आरोग्य मंत्री हेल्ल क्यूब (भीष्म) सेट की दो इकाइयां साँपी



නාගේය සම ගැනමිය සහ වා සේ සමයාගම් හදිද නිසි නිර් කුම්ක්රීමය පුණු සහ ගැනමි.එ සත් සිති ඒ සහපසුග් සම්ප්රාණයක් සහ ගලපාල .එද වෙනග්ග කියනා එ සම්ප්රාණය සම්ස් සමේක්රීමේ, रभट दभाव, भारत उर्जा वर्ष और गरिकामा के मामियों के जीवा भए दो केवर बामाओं।



मालदीव में आम का पौधा लगा

नई शिक्षा नीति छात्रों के समग्र विकास में अहम : मोदी भारत-ब्रिटेन में करार से कृषि एनईपी के पांच साल पूरे होने पर पीएम ने कहा-शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल जल्द करेंगे शुरू

मई दिल्ली। प्रधानमंत्री औद मोदी ने दा कि रिक्टले फाव क्वों में दिल्हा के क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाय हुए हैं। यां राष्ट्रीय शिक्षा पीत (एवांची) नामधार महीदन बदाबेद सामी के पापन और ब्युआपनी विकास में महत्वपूर्व सब दे रही है।

एनऐसे के पांच वर्ष पूरे होने पर स्थिता में, चीर्य मोदी ने करा क रित्या भंजालय मंगलबार को अधित भारतीय शिक्षा समागय एस) का आगोजन कर सा है और इस बार्यक्रम में दिखा



प्रधान आज करेंगे शिक्षा समागम का प्रमुघाटन प्रधान आनं अरंग विश्व वस्ताम का उत्पादन केट्रीम दिला गाँव भींद्र प्रधान मंत्रालया को उत्पादन पत्रतीय दिला सम्माम (प्रचीतपादस 2025) वा उत्पादन करेंगे: हाम मान्यम में विशा को अधिका मान्य, मालाक्ष्मीय, कोकात -प्राप्त कर्मा मान्य विभाग विमानी होता । हमारी ग्रेनास्त के अवसारी के साथ प्रचीतिक कर्मा है पत्रीकृत नारने कर जीव दिखा साथ, प्रवीत मान्य की प्रचीत्रक नार के पत्र दिखा प्रवास, प्रवीत मानुनीत्रका को मान्य कि प्रधान प्रवासन प्रचीत मानुनीत्रका को मान्य कि प्रधान प्रवासन प्रचीत मानुनीत्रका को मान्य कि प्रधान

आर्थिकोर और राष्ट्र को बाराकत बनारी है। हमात उद्देश्य ऐसी शिक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करना है विसमी विद्यार्थी अपनी प्रति, धनात और सपने के अनुवार आरे बढ़

राष्ट्र । उन्योग की कहा तथा के अनुस कहा हों. उन्योगकों से कहा कि अनुस कहा में पारत एक भाग और किसीया राष्ट्र के दियोग की और तथी में बढ़ सह है। इस सीयर, हमार्थे पुचारों के आमानियाता दिवास और रचनामकत को बहुत्य देने में हासून रचनायकता का बहुतक दर में उपहुत्त्व तिश्वा चीठ-2020 की भूमिया महात्वपूर्व होती। तिश्वा सम्बाग्य उमारे बाह्य संस्थाप और सहस्रोग की भागा का प्रजीव है। पीरण पीठी में कहा, मुझे विश्वास है कि यह आयोजन में सिक्त काके प्रचीत के पथ पर अवसर है। पैएम ने बारा, विद्वाले पांच वर्षे में रिक्षा के क्षेत्र में अनेक सकारायक हर संबद्धते को अपनी संतीतन तमें संबद्धते को अपनी संतीतन तमें, रामगीतने और उपलब्धियों साम्रा करने का अवसर प्रदान मदलाम हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसंदान और नमाचार को

औररोजगारकोबढावामिलेगा

अद्वितीय किंदा यूनेस्को सूची में भारत की ४४वीं धरोहर शिवनेरी छत्रपति शिवाजी की जन्मस्थली। प्रतापगढ छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1659 में प्रतापगढ़ के युद्ध में बीजापुर की सेना को हराकर अफजल खान का अंत किया। रायगढ मराठा द्वारा जीते गए प्रारंभिक किलों में से एक, 1674 में छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक, स्वराज्य की पहली राजधानी।

लोहागढ़



छत्रपति शिवाजी महाराज ने १६७० में किले पर विजय

रवंडेरी



१६७९ में मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी ने तटीय निगरानी के लिए खंडेरी द्वीप का निर्माण कराया।

सलहेर



वर्ष १६७१ में मराठों और मुगलों के युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को जीता।

राजगढ

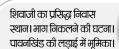


मराठा साम्राज्य के शासन-विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका। रायगढ़ से पहले मराठा साम्राज्य की राजधानी।

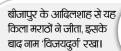
सुवर्णढूर्ग

१६६९ में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस द्वीप किले को सुदृढ़ किया।

पन्हाला



विजयदूर्ग

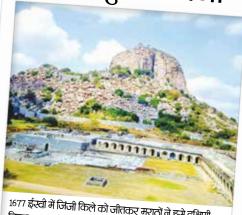


सिंधुढूर्ग

शिवाजी ने लगभग 1 करोड़ होन की लागत से नौसैनिक किले का निर्माण कराया।



तमिलनाडु का जिंजी



1677 ईस्वी में जिजी किले को जीतकर मराठों ने इसे दक्षिणी विस्तार का प्रमुख आधार बना लिया। शिवाजी का निवास भी रहा।







आर.एन.आई, DELHIN/2020/78812, 16-31 अगस्त, 2025

आरएनआई DELHIN/2020/78812, दिल्ली पोस्टल लाइसेंस नंबर- DL (\$)-1/3550/2023-25 डब्ल्यूपीपी संख्या- U (\$)-98/2023-25, posting at BPC, Market Road, New Delhi - 110001 on 13-17 advance Fortnightly (प्रकाशन तिथि- 4 अगस्त 2025, कुल पृष्ठ-60)

प्रधान संपादकः धीरेन्द्र ओझा. प्रधान महानिदेशक. पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक और मुद्रकः कंचन प्रसाद, महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्युरो, सूचना भवन, द्वितीय तल, नई दिल्ली- 110003 से प्रकाशित

मुद्रणः जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा. लि., बी-278, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020